राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 05 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-278 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

'हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, इसके खिलाफ हैं'

- हुमांयू कबीर को निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का पहला बयान

कोलकाता (एजेंसी)। टीएमसी विधायक हुमांयू कबीर को पार्टी से निलंबित करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक रैली में कहा कि हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के लोग दंगों की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम विधायक हुमांयू कबीर को निलंबित किए जाने का ऐलान करते हुए टीएमसी के सीनियर नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि उनका व्यवहार ऐसे समय में घोर गैर अनुशासनात्मक है, जब पार्टी राज्य में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए काम कर रही है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हाकिम ने कहा, कबीर सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त हैं, जिसके टीएमसी सख्त खिलाफ है। टीएमसी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। अब उनका पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उन्हें निलंबित किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है।

- बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक सस्पेंड

मस्जिद जरूर बनेगी अपनी बात पर कायम

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इसकी जानकारी दी। मेयर ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं ने कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करूंगा। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों (टीएमसी और भाजपा) के खिलाफ चुनाव लडूंगा। मुर्शिदाबाद जिले में 28 नवंबर को कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए थे। इन पर लिखा था कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा, मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करूंगा। यह मेरा निजी मामला है। किसी पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मुझे पहले भी 2015 में छह साल के लिए निलंबित किया था। अब फिर, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। वे जो करना चाहें, करें। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से हमारे एक विधायक ने अचानक बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिया। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों।

धर्मशाला में सरकार के खिलाफ बीजेपी की हुंकार रैली

राधे-राधे की गूंज,श्रीकांत बोले- राहुल गांधी को खुश करने के लिए सनातन का अपमान

धर्मशाला (एजेंसी)। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में गुरुवार को हुंकार रैली की। इसमें राधे-राधे की गूंज देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा- जब भी हम (विपक्ष) सदन में जाते हैं तो राधे-राधे बोलते हैं। इससे, सीएम सुक्खू भी राधे-राधे बोलने को मजबूर हो गए। जयराम ने कहा- अच्छा लगा कि सनातन का कुछ अंश इनमें भी आ गया। इन्होंने (सीएम) सत्ता में आते ही सनातन का अपमान शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा- आज हर कोने से बदलो बदलो, भ्रष्ट सरकार, यही आवाज आ रही है। उन्होंने कहा, हिमाचल सीएम सुक्खू अपनी ऑल्टो कार में बजट पेश करने आते हैं। साल 2027 के चुनाव में भी पूरी कांग्रेस ऑल्टो में फिट हो जाएगी। उन्होंने कहा- केंद्र सरकार आपदा के लिए 5500 करोड़ पहले दे चुकी है। सरकार पहले उसका हिसाब दें। फिर 1500 करोड़ की मांगे। सुक्खू सरकार चाह रही है कि 1500 करोड़ ट्रेजरी में नहीं, उनके खाते में आए। उन्होंने कहा- हिमाचल पहले ही ऑन सेल है। अब लैंड सिलिंग एक्ट की धारा 118 को कल विधानसभा में बिल लाकर बदला जा रहा है। उन्होंने कहा- जोरावर स्टेडियम में ही बीते कल बीजेपी ने मार्च निकाला था। अनावश्यक रूप से लाठीचार्ज करके लहूलुहान कर दिया। 10 बच्चे घायल कर दिए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा- सुक्खू सरकार सनातन का अपमान कर रही है। बच्चों को राधे-राधे बोलने से रोक रही है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के लिए भारत पहुंचे

पीएम मोदी ने किया स्वागत

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के लिए भारत पहुंच गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन का गले मिलकर स्वागत किया। यूक्रेन के साथ युद्ध होने के बाद उनका यह पहला भारत दौरा है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है। भारत सरकार के सूत्र के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में बहुत मददगार होगा। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बिजनेसमैन का एक बड़ा ग्रुप भी भारत आ रहा है। भारत को रूस के साथ व्यापार को बेहतर बनाने की उम्मीद है। रूस के साथ भारतीय एक्सपोर्ट बढ़ने की भी संभावना है, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मरीन प्रोडक्ट्स शामिल हैं। भारतीय बिजनेस और प्रोडक्ट्स को एक बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और हमारे किसानों की भलाई भी होगी।

राष्ट्रपति पुतिन के दौरे में भारत को रूस के साथ व्यापार को बेहतर बनाने की उम्मीद है। रूस के साथ भारतीय एक्सपोर्ट बढ़ने की भी संभावना है, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और मरीन प्रोडक्ट्स शामिल हैं। भारतीय बिजनेस और प्रोडक्ट्स को एक बड़ा बाजार मिलेगा, जिससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे और किसानों की भलाई भी होगी।

भारत और रूस के बीच शिपिंग, हेल्थकेयर, फर्टिलाइजर, और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई समझौते और एमओयू होने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों, गतिशीलता साझेदारी, संस्कृति, और वैज्ञानिक सहयोग में भी ज्यादा सहयोग देखने को मिलेगा।

पुतिन इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय समिट में भी शामिल होंगे।

वहीं, पीएम मोदी और पुतिन के बीच 5 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। फिर वह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे हैदराबाद में 23वीं वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय समिट शुरू होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, स्पेस और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा।

जानबूझकर विदेशी गणमान्य लोगों को विपक्ष से मिलने से रोकती है सरकार

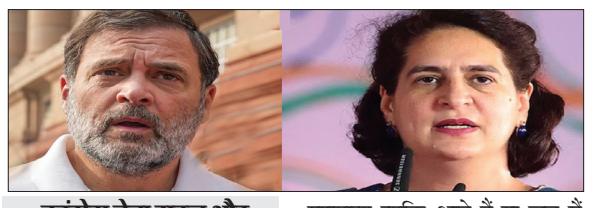

-कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद परिसर में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को विपक्ष, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष से मिलने से रोकती है। यह बात राहुल गांधी द्वारा तब कही गई है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भारत आ रहे है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो भी बाहर से आते हैं, उनकी नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है, यह परंपरा रही है...लेकिन आजकल यह होता कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए, तो यह उनकी नीति है...ये हर बार ऐसा करते हैं...संबंध तो सबके साथ है...हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं सिर्फ सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें।

वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं लेकिन इस प्रोटोकॉल का उल्टा होता है। इस सरकार की सभी नीतियां इसी आधार पर हैं...वो किसी और आवाज को उठने नहीं देना चाहते हैं और किसी और का पक्ष सुनना नहीं चाहते। वो प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं।

राज्यपाल के पहले अभिभाषण में ही बिगड़ गया माइक सिस्टम

- बिहार में हो गया खेला,13 करोड़ का माइक सिस्टम फेल

पेपरलेस विस के पहले सत्र में टैबलेट ऑन तक नहीं हुआ

पटना (एजेंसी)। 18वीं विधानसभा के लिए चुनकर आए विधायकों के लिए विधानसभा को हाइटेक किया गया। 30 करोड़ रुपए खर्च कर टैबलेट-नए माइक लगे, लेकिन बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभिभाषण देने पहुंचे तो माइक सिस्टम फेल हो गया। जिन टैबलेट की बड़ी चर्चा रही। कहा गया कि विधानसभा पेपरलेस हो गया है, वे भी तीन दिन से ऑन नहीं हुए। विधानसभा की पूरी कार्यवाही पहले की तरह कागजी हड्डुई। अध्यादेश पेश करने से लेकर स्पीकर के अभिभाषण तक, सारे काम पेपर से हुए। नए विधायकों के स्वागत के लिए विधानसभा को हाईटेक बनाया गया था। सेंसर वाले माइक से लेकर विधायकों की सीट के आगे टैबलेट लगाए गए। विधानसभा सूत्रों की माने तो नेशनल ई विधानसभा ऐप के ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत इस प्रक्रिया में लगभग 30 करोड़ रुपए

खर्च किए गए। 13 करोड़ रुपए अकेले माइक सिस्टम दुरुस्त करने पर खर्च हुए। इसकी क्वालिटी का आलम ये रहा कि सत्र के दौरान राज्यपाल के पहले अभिभाषण में ही पूरा सिस्टम बिगड़ गया।

बीएलओ की मौत पर राज्य सरकारों को फटकार,

जहां 10,000...वहां 30,000 स्टाफ भी तैनात हो सकता

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काम में असमर्थ बीएलओ की जगह दूसरे अधिकारी नियुक्त करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के तौर पर काम कर रहे कई पुरुषों और महिलाओं की मौत और आत्महत्या पर गंभीर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान बीएलओ की दिक्कतों को कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने संबंधित राज्यों को एसआईआर ड्यूटी के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने का आदेश दे दिया है। ताकि एसआईआर में लगे लोगों के काम के घंटे कम हो सकें और उन पर मानसिक बोझ खत्म कर सके। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ किया कि अगर बूथ लेवल ऑफिसर्स किसी खास वजहों का हवाला देकर छुट्टी मांगते हैं, तब उस पर केस-टू-केस बेसिस पर विचार होना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बीएलओ के काम करने के हालात और मेंटल हेल्थ के लिए राज्य सरकारों को

जिम्मेदार ठहराया, और कहा कि जहां 10,000 स्टाफ तैनात हैं, वहां 30,000 स्टाफ भी तैनात हो सकते हैं? शीर्ष अदालत ने राज्यों को फटकार लगाकर पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि जो बीएलओ ड्यूटी से छूट मांग रहे हैं, खासकर अगर वे बीमार हैं या किसी और वजह से असमर्थ हैं, तब उन्हें छुट्टी दें और उनकी जगह किसी और को रखा जाए। शीर्ष अदालत ने बीएलओ को बड़ी राहत देकर कहा कि अगर राज्य की तरफ से ऐसी राहत नहीं मिलती है, तब संबंधित बीएलओ कोर्ट से सीधे संपर्क कर सकता है। शीर्ष अदालत के ये निर्देश अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम की याचिका के बाद आए हैं, जिसके अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने की उम्मीद है।

टीवीके ने कई बीएलओ की मौत पर हुए विवाद के बीच कोर्ट का रुख किया था। तमिल पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि 35 से 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 32 के तहत बीएलओ को जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर रहा है।

वहीं टीवीके ने अपनी याचिका में तर्क दिया, 'हर राज्य में इसतरह के परिवार हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं या माता-पिता अलग हो गए हैंज क्योंकि आयोग सेक्शन 32 के नोटिस भेज रहा है।' याचिका में मौत या आत्महत्या करने वाले बीएलओ के परिजनों के लिए मुआवज़े की भी मांग की गई है। पार्टी ने कहा, ज्अभी बस यही अनुरोध है कि आयोग ऐसी सख्त कार्रवाई न करे। पार्टी ने दावा किया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीएलओ के खिलाफ 50 से ज़्यादा पुलिस केस दर्ज किए गए हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत की मतदाताओं को खुली धमकी...

- विवादित बयान हो रहा वायरल : वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो बंद होगा राशन-पानी

सागर (एजेंसी)। सागर में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं जुड़वाए जाएंगे, उन्हें राशन सहित सरकारी सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बार मतदाता सूची में नाम जोडने की प्रक्रिया अलग तरीके से की जा रही है, इसलिए सभी लोग इसका विशेष ध्यान रखें।

मंत्री गोविंद राजपूत सुरखी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। उनके इस बयान को लेकर अब सोशल मीडिया में चर्चा तेज हो गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अभी गांव में मतदाता सूची में नाम जुडने का काम चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लें। कोई कि मतदाता सूची में इस पर नाम अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वाओगे तो आपको राशन, आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। 5-6 दिन का समय है। आगे मंत्री ने कहा कि समय निकालकर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। हमारा भी नाम जुड़

रहा था, हमने अपना फॉर्म जमा कर दिया हैं। मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बना हुआ है, क्योंकि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पारदर्शी बनाना है। इस अभियान में सभी योग्य वोटर्स को लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

क्या सच में कट जाएगा राशन?

मंत्री के बयान के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने पर राशन कार्ड या सरकारी लाभ बंद कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को सुधारना, अपडेट करना और गलत प्रविष्टियों को हटाना होता है। इसका राशन कार्ड या अन्य सरकारी योजनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, यह वीडियो 3-4 दिन पुराना है। जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर, सागर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआइआर में मतदाता सूची सटीक बनाने लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो सके। जिले में दैनिक प्रगति दर्ज की जा रही है, बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। मतदाताओं की फॉर्म भरवाने में मदद भी कर रहे हैं।

आयोग के अधिकारी बन गए: कटारे

बयान सामने आने के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोल दिया और आरोप लगाया कि मतदाता सूची को हथियार बनाकर लोगों को डराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी मंत्री के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर करारा प्रहार किया हैं। उन्होंने कहा कि नेतागिरी छोडक़र क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं? जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। किसका नाम जुड़ेगा किसका नहीं जुड़ेगा इससे गोविंद सिंह से क्या लेना देना? कटारे ने आगे कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग एसआईआर को प्रभावित कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अगर कोई धाराएं होती हो तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

भाजपा ने 2026 के चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में 13,000 बैठकों की योजना बनायी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2026 के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले पश्चिम बंगाल में कम से कम सात रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। भाजपा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि इन बड़ी रैलियों के अलावा, पार्टी की योजना शुक्रवार से शुरू होकर एक महीने से अधिक समय तक राज्य भर में 13,000 बड़ी और छोटी बैठकें आयोजित करने की है।

सिन्हा ने कहा, ''पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मोदी कम से कम सात रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि

केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता भी रैलियों को संबोधित करेंगे। रैलियों की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।'' उन्होंने बताया कि 13,000 बैठकों में से प्रत्येक के दौरान सात से आठ मतदान केंद्रों के मतदाताओं को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों तक पार्टी के विकासोन्मुख पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण को पहुंचाना है।

भाजपा नेता ने कहा कि यह अभियान पांच दिसंबर को शाम पांच बजे से सात बजे के बीच 'शक्ति केंद्रों' (पांच से सात मतदान केंद्रों के समूहों) के साथ शुरू होगा, जिन्हें स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेता संबोधित करेंगे। ऐसी बैठकें 15 जनवरी तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद, सांसदों और विधायकों सहित राज्य और केंद्रीय स्तर के नेताओं द्वारा विधानसभावार जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा और चुनाव नजदीक आने के साथ इसकी गति बढ़ने की उम्मीद है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संचार साथी पर राजनीति की आंधी के बीच साइबर सुरक्षा बनाम निजता की बहस

इस तरह संचार साथी को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस तकनीक, पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा के बीच संघर्ष को उभार रही है।सुरक्षा का नया औज़ार 'संचार साथी' का मूल उधेश्य है।भारत में हर साल लाखों मोबाइल चोरी या गुम हो जाते हैं। कई बार इन्हीं चोरी हुए मोबाइलों का इस्तेमाल अपराधी साइबर फॉड, फिशिंग और अवैध गतिविधियों में करते हैं। टेलीकॉम कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के पास भी चोरी हुए मोबाइलों का डेटा सीमित मात्रा में ही पहुँच पाता था।इसी कमी को दूर करने के लिए संचार साथी ऐप विकसित किया गया। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं।

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

भारत में डिजिटल क्रांति की रफ्तार जितनी तेज़ है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। इसी चुनौती से उपजे समाधानों में से एक है ,संचार साथी ऐप, जिसे दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2023 में लॉन्च किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा के औज़ार उपलब्ध कराना, खोए या चोरी हुए फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने में मदद करना, तथा साइबर फ्रॉड से बचाव को मजबूत करना है। बीते दो वर्षों में इस ऐप ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की।वेब पोर्टल के आँकड़ों के अनुसार 1.14 करोड़ से अधिक डाउनलोड और 42 लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक होने का दावा इसकी विश्वसनीयता और व्यापक उपयोग की कहानी खुद कहता है।लेकिन हाल ही में यह ऐप अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए कि नए हैंडसेट खरीदने वाले ग्राहकों को संचार साथी ऐप डाउनलोड कर इसकी जानकारी देना सुनिश्चित करें। बस, फिर क्या था,विपक्ष ने इसे तुरंत जासूसी का टूल करार दे दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे निजता पर सीधा हमला बताया, जबकि कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल और सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने भी सरकार के इस कदम को नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कहा। वहीं सरकार का कहना है कि ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है।जिसे डाउनलोड करना है करे, जिसे नहीं करना है न करे।

इस तरह संचार साथी को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस तकनीक, पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा के बीच संघर्ष को उभार रही है।सुरक्षा का नया औज़ार 'संचार साथी' का मूल उधेश्य है।भारत में हर साल लाखों मोबाइल चोरी या गुम हो जाते हैं। कई बार इन्हीं चोरी हुए मोबाइलों का इस्तेमाल अपराधी साइबर फॉड, फिशिंग और अवैध गतिविधियों में करते हैं। टेलीकॉम कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के पास भी चोरी हुए मोबाइलों का डेटा सीमित मात्रा में ही पहुँच पाता था।इसी कमी को दूर करने के लिए संचार साथी ऐप विकसित किया गया। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं।

मोबाइल चोरी-गुम होने पर तुरंत ब्लॉक कराने की सुविधा है।

फर्जी या अनजान मोबाइल कनेक्शन की पहचान हो सकती है।साइबर फॉड रिपोर्टिंग और सुरक्षा जागरूकता की उपब्धता।

सरकारी आँकड़े बताते हैं कि लाखों लोग इसकी मदद से अपने फोन ब्लॉक करा चुके हैं। इससे चोरों के लिए चोरी का फोन उपयोग करना जोखिम भरा हो गया है। कई राज्यों की पुलिस ने भी माना है कि इससे मोबाइल-चोरी गैंग पकड़ने में मदद मिली है।सरकार का पक्ष सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा है।

सरकार का तर्क है कि संचार साथी ऐप नागरिक सुरक्षा का साधन है, न कि निगरानी का औज़ार।टेलीकॉम विभाग कहता है।ऐप केवल आईएमईआई आधारित कार्य करता है, किसी व्यक्ति की निजी चैट, लोकेशन, फोटो या कॉल डेटा एकत्र नहीं करता है।यह केवल वही जानकारी उपयोग करता है जो मोबाइल नेटवर्क में पहले से मौजूद रहती है।डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए यह ऐप आवश्यक है।

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है।चाहें तो डाउनलोड करें, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं।सरकार के अनुसार संचार साथी आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के सुरक्षा मॉडल का आधार बन सकता है, जैसे आधार और यूपीआई ने पहचान और भुगतान व्यवस्था को मजबूत किया।विपक्ष का बेमतलब आरोप है कि यह ऐप सुरक्षा नहीं, जासूसी का माध्यम है।विपक्ष इस मुद्दे को निजता और सरकारी नियंत्रण के नजरिए से देख रहा है।कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रमुख आरोप हैं।सरकार ऐप के बहाने नागरिकों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है।यह निजता के अधिकार का संभावित उल्लंघन है।जनता को जबरन निगरानी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है।टेलीकॉम कंपनियों के जरिए ऐप डाउनलोड करवाना अप्रत्यक्ष दबाव है।प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सरकार डिजिटल जीवन में अनावश्यक दखल बढ़ा रही है। सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास ने इसेस्टेट सर्वेलेन्स का नया रूप बताया।

जनता किस तरफ?आज का दौर ऐसा है, जहाँ हर नागरिक दो बड़े सवालों के बीच खड़ा है।

क्या सुरक्षा के लिए कुछ निजता त्यागनी पड़ेगी?क्या सरकार को बिना अनुमति डिजिटल हस्तक्षेप करने की सीमा तय होनी चाहिए?संचार साथी ऐप के मामले में यही संघर्ष दिखाई दे रहा है।एक तरफ भारत में साइबर अपराध जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा उपकरणों की ज़रूरत स्पष्ट है। डिजिटल इंडिया में मोबाइल फोन अब केवल एक गैजेट नहीं, बल्कि पहचान, बैंकिंग, वित्तीय लेनदेन और व्यक्तिगत डाटा का केंद्र बन चुका है। सुरक्षा मजबूत करना समय की मांग है।

दूसरी तरफ, कई नागरिकों के मन में यह भी डर है कि कहीं सुरक्षा के नाम पर उनकी निजी जिंदगी का दायरा सीमित न हो जाए। दुनिया भर में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ सुरक्षा ऐप्स पर निगरानी के आरोप लगे। ऐसे में आशंका होना स्वाभाविक है।क्या राजनीति तकनीक के रास्ते में बाधा बन रही है?संचार साथी को लेकर हुआ विवाद बताता है कि देश में साइबर सुरक्षा भी राजनीतिक चश्मे से देखी जाने लगी है।

यदि सरकार कोई सुरक्षा उपाय लाती है, विपक्ष उसे निगरानी बताता है।यदि विपक्ष कोई डिजिटल अधिकारों से जुड़ा कदम उठाता है, सरकार उसे अवसरवाद कहती है।

हकीकत यह है कि तकनीक का मनुष्य से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं होता, लेकिन उसकी नीयत और उपयोग निश्चित रूप से राजनीति से प्रभावित हो सकता है।यहाँ समस्या ऐप नहीं, बल्कि विश्वास की है।क्या आवश्यक है?एक पारदर्शी डेटा नीति।

संचार साथी पर विवाद से एक स्पष्ट संदेश निकलता है।

भारत को अपनी सार्वजनिक डिजिटल सेवाओं के लिए एक स्पष्ट, कड़ा और पारदर्शी डेटा नीति चाहिए।डेटा कहाँ स्टोर होगा?किस तरह उपयोग होगा?

सरकार डेटा तक कब पहुँच सकती है? और नागरिक का डेटा मिटाने का अधिकार क्या होगा?

इन सवालों का उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। यदि सरकार इन पहलुओं पर मजबूत और भरोसेमंद नीति प्रस्तुत करे, तो किसी भी डिजिटल उपकरण पर संदेह स्वत: कम हो जाएगा।

देशहित क्या कहता है?यदि देखा जाए, तो संचार साथी ऐप सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी है। लाखों लोगों के मोबाइल ब्लॉक होना, डाउनलोड की बढ़ती संख्या, और पुलिस जांच में मदद मिलना इसके फायदे साबित करते हैं।

लेकिन सुरक्षा किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती।

यदि नागरिकों को लगता है कि उनके अधिकार खतरे में आ रहे हैं, तो यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।इसलिए जरूरी है कि सरकार और विपक्ष तकनीक को राजनीतिक हथियार न

बनाएं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और निजता दोनों को संतुलित करते हुए आगे बढ़ें।बहस से समाधान निकले, सनसनी नहीं।संचार साथी ऐप को लेकर मचा शोर तकनीकी बहस के बजाय राजनीतिक तूफान ज्यादा लगता है।

वास्तविकता यह है कि यह ऐप देश को एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण देने की दिशा में एक पहल है।लेकिन डिजिटल सुरक्षा और नागरिक निजता दो पहिये हैं

दोनों में तालमेल होना आवश्यक है। सरकार को पारदर्शिता के साथ विश्वास बढ़ाना होगा, और विपक्ष को प्रत्येक तकनीकी पहल को निगरानी का डर बताने से बचना चाहिए।देश के लिए सबसे अच्छा वही है, जिसमें सुरक्षा भी मिले और निजता भी सुरक्षित रहे। संचार साथी ऐप इसी दोराहे पर खड़ा है।यह बहस हमें बताती है कि डिजिटल भारत को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि विश्वास की राजनीति भी उतनी ही जरूरी है।

(रु 103 जलवन्त टाउनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार स्तम्भकार)

संपादकीय

'साथी' पर अविश्वास

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि आगामी वर्ष मार्च से हर नये स्मार्टफोन में 'संचार साथी' ऐप पहले इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर पुराने स्मार्ट फोनों में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा भेजा जाएगा। जिसको लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष का कहना था कि इससे निजता का उल्लंघन होगा और व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल, सरकार का कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप से नई तरह की असुरक्षा पैदा हो सकती है। बताया जाता है कि सरकार ने स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप इस तरह इंस्टाल करने को कहा था ताकि उसे डिलीट या अक्षम न किया जा सके। केंद्र की दलील थी कि यह ऐप उपभोक्ता को धोखाधड़ी वाले फोन और संदेशों की रिपोर्ट लिखवाने में मदद करता। साथ ही चोरी किए गए मोबाइल की बरामदगी आसान हो पाती। लेकिन निजी डेटा सुरक्षा व इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके चलते इसका विरोध हुआ। वैसे सर्च इंजन में पहले से मौजूद इस ऐप को देश के लाखों लोग पहले ही स्वेच्छा से डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन इसको अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश के बाद विरोध के स्वर उभरने लगे। जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके जरिये व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करके उसके जीवन में ताक-झांक की जा सकती है। हालांकि, विरोध के सुर मुखर होने के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया कि यह निर्णय वैकल्पिक है और कोई व्यक्ति इस ऐप को इच्छानुसार डिलीट कर सकता है। निस्संदेह, निजता हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे में किसी ऐप की अनिवार्यता से व्यक्ति की गोपनीयता में खलल पड़ने की आशंका जतायी जाने लगी। पिछले दिनों सरकार ने व्हाट्स ऐप व टेलीग्राम आदि कम्युनिकेशन ऐप्स संचालक कंपनियों से कहा था कि वे अपनी सेवा को मोबाइल के सिम कार्ड से जोड़कर रखें। ताकि सिम के बिना इन ऐप का दुरुपयोग न हो सके। जिसको लेकर टेलि-कम्युनिकेशन कंपनियों ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया था। निस्संदेह, निजता का अधिकार देश में मौलिक अधिकार के रूप में मौजूद है। शीर्ष अदालत ने भी अपने एक निर्णय के जरिये स्पष्ट किया था कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 में 'राइट टू प्राइवेसी' में भी निहित है। जिसके अंतर्गत मोबाइल, इंटरनेट व डिजिटल जानकारियां भी शामिल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से इतर व्यक्ति को अपनी डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा का हक है। यही वजह है कि विगत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोबाइल व निजी कंपनियां उपभोक्ता से आधार कार्ड नहीं मांग सकती। इस फैसले को तब निजता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। यही वजह है कि 'संचार साथी' की अनिवार्यता के बाद निजता व व्यक्ति के डेटा में सरकारी दखल को लेकर सवाल उठने लगे। निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है।

स्वयंसेवा वह सॉफ्टवेयर जो दुनिया को क्रैश होने से बचाता है

(लेखक- दिलीप कुमार पाठक)

(05 दिसम्बर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 5 दिसंबर को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण, निस्वार्थ योगदान को स्वीकार करने और उसे बढ़ावा देने का एक वैश्विक अवसर है।समाज में स्वयंसेवा की आवश्यकता और महत्व से हम सभी भली-भांति परिचित हैं। जब कोरोना महामारी, विनाशकारी बाढ़, भूकंप जैसी भीषण आपदाएं आती हैं, तब सरकारी तंत्र के साथ-साथ स्वयंसेवक ही तत्काल राहत की बागडोर संभालते हैं। वे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समाज की सामूहिक जम्मिेदारी का निर्वहन करते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार अकेले हर चुनौती का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती। स्वयंसेवा केवल संकटकालीन प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है; यह सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करती है, हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाती है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नागरिकों में जम्मिेदारी की भावना जागृत करती है और मानवीय एकजुटता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है।

यह पहल स्वयंसेवा के माध्यम से समग्र मानवता की बेहतरी के लिए बदलाव लाने की सामूहिक क्षमता की एक याद दिलाती है। यह विशेष दिन उन अनगिनत व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो निस्वार्थ सेवा के लिए अपना बहुमूल्य समय समाज एवं मानवता के लिए समर्पित करते हैं। कई चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद, वे अक्सर बिना किसी प्रचार या पहचान के अपना महत्वपूर्ण कार्य जारी रखते हैं। ये सभी स्वयंसेवक समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास करते हैं, और यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश स्वयंसेवक अवैतनिक होते हैं, मतलब उन्हें इसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता, बस समाज प्रेम का एक ज़ज्बा होता हैद्य

उनके कार्यों में विविधता शामिल है, जैसे जानवरों को बचाना, बुजुर्गों की सहायता करना, गरीबों की मदद करना और वंचितों को शिक्षित करना। विश्व स्तर पर, एक अरब से भी अधिक लोग अपने समुदायों को बेहतर बनाने के लिए अपना समय, प्रतिभा और ज्ञान का योगदान देते हैं। स्वयंसेवक समाज के हर स्तर और क्षेत्र में मौजूद हैं — वे वंचित बच्चों और वयस्कों को व्यावहारिक देखभाल प्रदान करने से लेकर जटिल तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह देने तक, हर तरह से मदद करते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ कुछ अनूठा कौशल और अनुभव लेकर आता है, जिससे सामूहिक प्रयास और मजबूत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव ने इस विशेष दिन पर स्वयंसेवकों के अमूल्य योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि वे विकास चुनौतियों और आम भलाई के लिए ठोस और व्यावहारिक समाधान लेकर आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा वैश्विक स्तर पर स्वयंसेवकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदानों को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाली पहली संस्था थी। मानवीय प्रयासों और सतत आर्थिक व सामाजिक विकास में स्वयंसेवा की शक्ति को स्वीकार करते हुए, महासभा ने 17 दिसंबर 1985 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव 40/212 अपनाया। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, हर साल 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में नामित किया गया। यह दिवस स्वयंसेवकों से जुड़े संगठनों और व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को स्वयंसेवा के महत्व को बढ़ावा देने, सरकारों को इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के स्वयंसेवकों के समर्पण को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक कार्यक्रम जैसे संस्थानों ने स्वयंसेवी कार्य के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस वैश्विक उत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के लाखों स्वयंसेवकों को श्रद्धांजलि देना है, जो गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपना बहुमूल्य समय और प्रयास स्वेच्छा से समर्पित करते हैं। नतीजतन, आज दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग सक्रिय रूप से विभिन्न स्तरों (स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) पर स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जिससे समुदायों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

स्वयं सेवा से जुड़े लोगों का उद्देश्य बहुत विशाल है, जो बेहतर दुनिया के लिए संकल्पित है, जैसे गरीबी समाप्त करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा स्थापित करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, एचआईवी/एड्स, मलेरिया, डेंगू और अन्य गंभीर बीमारियों के प्रसार को रोकना, साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। हम सभी को उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनका काम दूसरों को खुश करता है और हमें सुरक्षित रखता है। हम इस दिन इन सामाजिक चेतना सम्पन्न एवं समाज के लिए संकल्पित लोगों का सम्मान करते हैं।

अपना दृष्टिकोण

चिंतन मनन

एक कन्या ने अपने पिता से कहा, मैं किसी पुरातत्वविद् से विवाह करना चाहती हूं। पिता ने पूछा, क्यों? कन्या बोली, पिताजी! पुरातत्वविद् ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पुरानी चीजों को ज्यादा मूल्य देता है। मैं भी ज्यों-ज्यों पुरानी होती जाऊंगी, बूढ़ी होती जाऊंगी, मेरा मूल्य भी बढ़ता जाएगा। वह मेरे से नफरत भी नहीं करेगा। पुरातत्वविद् यह नहीं देखता कि वस्तु कितनी सुन्दर है, कितनी असुन्दर है। वह इतना देखता है कि वस्तु कितनी पुरानी है। यह उसके मूल्यांकन की दृष्टि होती है।

कहने का अर्थ यह कि मूल्यांकन का अपना-अपना दृष्टिकोण होता है। मूल्यांकन का हमारा भी एक दृष्टिकोण है। अध्यात्म की साधना करने वाले व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है मूल्यांकन का और वह उसका स्वयं का दृष्टिकोण होता है, किसी से उधार लिया हुआ नहीं। उसका दृष्टिकोण बदले, चरित्र बदले। वह पुराना ही न रहे, नया बने। पुरानेपन का आग्रह छूटे। साधना में पुरातत्वविद् की दृष्टि काम नहीं देती। वहां नयेपन का आयाम खुलता है और सदा नया बना रहने की आकांक्षा बनी रहती है।

प्रत्येक समझदार आदमी का प्रयत्न सप्रयोजन होता है। ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति का साध्य है- रूपान्तरण दृष्टि का रूपान्तरण, चरित्र का रूपान्तरण। अहं को अर्हम् में बदलना। अहं और अर्हम् में केवल एक मात्रा का अन्तर है। साधक अहं को छोड़कर अर्हम् बनना चाहता है। एक मात्रा का अर्जन करना है। अहम् पर ऊर्ध्व र लगे, ऐसा प्रयत्न करना है। तब साधना सफल हो जाती है।

विचार मंथन

नाम बदलने की राजनीति अर्थात् चमकते शब्द, छिपते सवाल

(लेखक- सनत जैन)

देश में जब नवनिर्माण की जगह पुराने स्थलों के नाम बदलने का उपक्रम किया जाने लगे तब सियासी माहौल गर्मा ही जाता है। दरअसल इन दिनों राजनीतिक विमर्श काफी हद तक नाम बदलने की राजनीति पर केंद्रित नजर आ रहा है। शहरों और मोहल्लों के साथ ही अब सरकारी भवनों, परिसरों और उच्च पदों से जुड़े स्थलों के नाम बदलने की कवायद तेज है। प्रधानमंत्री आवास को सेवातीर्थ और राजभवनों को लोक भवन कहने की पहल, कागज़ पर आकर्षक भले लगे, लेकिन इससे जुड़े असल सवाल और भी गहरे हैं। क्या केवल नाम बदल देने से संस्थाओं की प्रकृति बदल जाती है? क्या शब्दों के आवरण से व्यवस्था की खामियाँ ढक सकती हैं? यही वे प्रश्न हैं जिन पर समाज और विशेषज्ञ अब खुलकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिनेश केवरा ने कहा, नाम बदलने से काम नहीं बदलते। उनका यह कथन सही मायने में इस पूरे प्रतीकात्मक राजनीतिक विमर्श का सार कहा जा सकता है। यहां समझना होगा कि इस तरह की तमाम आपत्तियां नामों से नहीं, बल्कि उन नामों के पीछे छिपे वास्तविकता विरोध से है। लोक भवन कहे जाने वाले राजभवन वास्तविक अर्थों में चाहे कुछ भी हों, परन्तु जनता के लिए वे कितने खुले हैं? इसी प्रकार सेवातीर्थ जैसे आध्यात्मिक और पवित्र शब्द का प्रयोग क्या उस स्थान को तीर्थ बना देता है? क्या भव्य सुरक्षा, प्रतिबंधित प्रवेश और सत्ता का केन्द्रीयकरण जनता के लिए सेवा की भावना को प्रतिबिंबित करता है? इन प्रश्नों के उत्तर सहज ही स्पष्ट कर देते हैं कि नाम और वास्तविकता के बीच की खाई कितनी गहरी है। लोकतंत्र में मूल सवाल पूर्व नामों को बदलने का नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का है। जनता यह देखना चाहती है कि सरकारी संस्थाएँ उनके लिए कितनी सुलभ, संवेदनशील और उत्तरदायी हैं, न कि उनका नाम कितना आध्यात्मिक या आकर्षक है। जब महंगाई और बढ़ते अपराध के आकंड़े समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और न्याय जैसी बुनियादी समस्याएँ जस की तस बनी हुई हों, तो नाम बदलकर उत्पन्न की गई चमक केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका ही प्रतीत होती है। ऐसे में यह कहना कहां गलत साबित होता है, कि आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग राजनीतिक ब्रांडिंग का साधन बनता जा रहा है। यह प्रवृत्ति केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं, बल्कि भाषणों, कार्यक्रमों और सरकारी अभियानों तक फैली हुई है। शब्दों की चमक बढ़ने से शासन की गुणवत्ता नहीं बढ़ती; और जनता अब इस अंतर को भलीभाँति समझ रही है। इसलिए नामकरण की राजनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जनता दो-जून की रोटी के लिए त्रस्त है, छोटी-छोटी समस्याएं भी अब पहाड़ सरीखी हो चुकी हैं लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। जनता समझ रही है कि नाम बदलने से काम नहीं बदल जाते, इसलिए अब वो भी मुखर हो रही है। प्रधानमंत्री की जीवनशैली और सरकारी भव्यता को लेकर जनता द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से अन्य मंचों पर बहस का कारण बने हुए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि जब लोक कल्याण मार्ग के नाम के साथ करोड़ों की लागत वाला हाई-टेक परिसर, आधुनिक विमान और सुरक्षा तंत्र जुड़ जाता है, तो सादगी का संदेश निष्प्रभावी हो जाता है। यह केवल विरोधियों की आलोचना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टिकोण से उठे तर्कसंगत प्रश्न हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक भी मानने लगे हैं कि इस प्रकार से नाम बदलना प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा है, जो जनता को यह आभास देने का प्रयास है कि सरकार सक्रिय है, जबकि वास्तविक सुधारों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी संस्थान की आत्मा उसके नाम में नहीं, उसके कार्य और व्यवहार में होती है। यदि सरकारी प्रक्रियाएँ पारदर्शी नहीं हैं, यदि आम नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है, तो भव्य नामों का कोई वास्तविक महत्व नहीं। इतिहास गवाई है कि शासकों की पहचान उनके राजमहलों के नामों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से होती रही है। जनता उस शासन को याद रखती है जिसने उसके जीवन को बेहतर बनाया हो, न कि उस शासन को जिसने केवल नामों की अदला-बदली की हो। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार प्रतीकवाद से अपने आप को निकाले और वास्तविक धरातल पर कार्य करते हुए आमजन का दिल जीते। नाम बदलना आसान है, पर व्यवस्था बदलना कठिन। जनता उन बदलावों की अपेक्षा करती है जो उसके जीवन में प्रत्यक्ष सुधार लाएँ, महंगाई से राहत जिसका मोदी सरकार ने वादा किया हुआ है, बेहतर स्कूल, सस्ता इलाज, सुरक्षित रोजगार, किसानों को राहत और न्याय की सुगम पहुँच।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत में हेलीकॉप्टर किराए की मांग बढ़ी

- छोटे हेलीकॉप्टर का प्रति घंटा किराया 94,400 से 1.5 लाख रुपए तक

नई दिल्ली । भारत में हेलीकॉप्टर किराए पर लेना अब केवल फिल्मों या लग्जरी तक सीमित नहीं रहा। वीआईपी यात्रा, शादियां, एडवेंचर टूर और इमरजेंसी मेडिकल जरूरतों के लिए इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। छोटे हेलीकॉप्टर (सिंगल इंजन) में 3-4 लोग बैठ सकते हैं, और प्रति घंटा किराया 94,400 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक है। बड़े हेलीकॉप्टर (डबल इंजन) में 6-8 लोग बैठते हैं, और किराया 3 लाख से 4 लाख रुपए तक होता है। डबल इंजन मॉडल लंबी दूरी और सुरक्षा के लिहाज से अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। कंपनियां दूरी के बजाय उड़ान के समय के हिसाब से चार्ज करती हैं। लैंडिंग और पार्किंग फीस, विशेष सर्टिफिकेशन, ईंधन लागत, इवेंट व्यवस्थाएं और पीक सीजन के कारण किराया बढ़ सकता है। छोटे हेलीकॉप्टर सस्ते और छोटी दूरी के लिए उपयुक्त हैं, जबकि बड़े हेलीकॉप्टर लंबी दूरी और अधिक सुरक्षा के लिए।

भारत-कनाडा ने फिर से शुरू की मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता

नई दिल्ली । भारत और कनाडा ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, कंप्रेहें सिव इकानॉमी पार्टनरे शिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर बातचीत फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस समझौते की रूपरेखा, उद्देश्य और कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। सीईपीए के तहत वस्तुओं पर शुल्क में कटौती या समाप्ति, कुशल पेशेवरों की आवाजाही में आसानी और निवेश आकर्षित करना शामिल है। गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने समग्र दृष्टिकोण और प्रारंभिक रूपरेखा पर विचार साझा किया। 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और वार्ता रोक दी गई थी। इससे पहले प्रस्तावित समझौते पर दोनों देशों के बीच छह से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी थी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने अडाणी-गूगल एआई डेटा सेंटर के लिए 480 एकड़ जमीन आवंटित की

- परियोजना चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी और सरकार 22,000 करोड़ तक प्रोत्साहन भी देगी

अमरावती . आंध्र प्रदेश सरकार ने गूगल की कंपनी रैडेन इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में 480 एकड़ भूमि आवंटित की है। भूमि आवंटन अदाणी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को 'प्राथमिक अधिसूचित भागीदार' के रूप में किया गया है। अन्य अधिसूचित भागीदारों में अदाणी कॉनेक्स, अदाणी पावर, भारती एयरटेल और नेक्सट्रा डेटा/विजाग शामिल हैं। यह आवंटन अंतिम सर्वेक्षण के पूरा होने पर लागू होगा। रैडेन एआई डेटा सेंटर का कुल निवेश 15 अरब डॉलर (लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। परियोजना चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी और सरकार से 22,000 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहनों का आश्वासन दिया है। डेटा सेंटर गूगल की सेवाओं जैसे सर्च, यूट्यूब और वर्कस्पेस के संचालन मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी, जो पूर्ण संचालन पर मुंबई की वार्षिक बिजली खपत का लगभग 50 प्रतिशत उपयोग करेगा। परियोजना आंध्र प्रदेश में डिजिटल और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देगी, नई नौकरियां सृजित करेगी और राज्य की वैश्विक तकनीकी छवि मजबूत करेगी। रैडेन के साथ अधिसूचित भागीदार सभी प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकेंगे। सरकारी आदेश 2 दिसंबर 2025 को जारी किया गया और इसमें मंत्रिपरिषद की 28 नवंबर की बैठक में प्रस्ताव की मंजूरी का उल्लेख किया गया है।

शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद

आईटी, ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा शेयरों में आया उछाल

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच ही आई टी सहित दिग्गज कंपनियां के शेयरों में खरीददारी हावी होने से दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में 158.51 अंक बढ़कर 85,265.32 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 47.75 अंक ऊपर आकर 26,033.75 पर बंद हुआ । आज आईटी शेयरों में निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.41 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल और रियल्टी शेयरों में भी तेजी रही। दूसरीओर एनर्जी,मीडिया, इन्फ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस लाल निशान में बंद हुआ।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में सपाट कारोबार हुआ। ऐसे में अधिकतर शेययरों में गिरावट रही। । निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 15.85 अंक फिसलक 60,299.80 और निफ्टी स्मॉलकैप 41.60 अंक नीचे आकर 17,607.85 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टीसीएस,टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, सन फार्मा, बीईएल, ट्रेंट,आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, एक्सिस बैंक, एचयूएल, पावर ग्रिड और एशियन पेंट्स के शेयरों में बढ़त रही जबकि मारुति सुजुकी,महिंद्रा बैंक, टाइटन, एसबीआई,आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के शेयर गिरे हैं।

इससे पहले आल सुबह बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद प्रमुख सूचकांकों ने तेजी पकड़ ली। सेंसेक्स की 84,987 अंकों पर गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई। एनएसई का निफ्टी-50 भी कमजोर शुरुआत के साथ 25,981 पर खुला था। हालांकि, खुलने के कुछ ही देर बाद इसमें सुधार देखने को मिला।

ऐ शियाई बाजार- एशिया बाजारों में वॉल स्ट्रीट में रोजगार आंकड़ों के कारण बढ़त के बाद बाजारों में मिलाजुला रुख रहा।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभाला

- 2025 में अब तक एफपीआई ने कैश सेगमेंट से रिकॉर्ड 17.3 बिलियन डॉलर निकाले

मुंबई ।

दिसंबर के पहले तीन सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयर बाजार में लगभग 8,369 करोड़ रुपए (933 मिलियन डॉलर) की शुद्ध बिकवाली की। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में अब तक एफपीआई ने कैश सेगमेंट से रिकॉर्ड 17.3 बिलियन डॉलर की निकासी की है। पिछले महीनों में भी बिकवाली का क्रम जारी रहा, नवंबर में 3,765 करोड़, सितंबर में 23,885 करोड़ और अगस्त में 34,990 करोड़ रुपए। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय बाजार का ऊंचा वैल्यूएशन विदेशी निवेशकों को अपेक्षाकृत सस्ते बाजारों की ओर मोड़ रहा है। एफपीआई की बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों की मजबूती ने बाजार को स्थिर रखा। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से नवंबर 2025 तक म्यूचुअल फंडों में एसआईपी के जरिए 2.75 लाख करोड़ से अधिक का ग्रॉस इनफ्लो आया। इस लगातार निवेश ने सेंसेक्स और निफ्टी को विदेशी बिकवाली के दबाव से बचाया। 27 नवंबर को सेंसेक्स ने 14 महीने बाद 86,159 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर को पार किया। हालांकि, इसके बाद लगातार चार सत्रों में बिकवाली के कारण सूचकांक 1,000 अंक से अधिक फिसलकर 85,107 पर बंद हुआ। अधिकांश सेक्टर्स में गिरावट देखी गई, लेकिन आईटी सेक्टर ने मजबूती बनाए रखी। गौरतलब है कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ी है, लेकिन घरेलू निवेशकों की सक्रिय भूमिका ने बाजार को संतुलित रखा है। रुपया दबाव में है, लेकिन घरेलू निवेश की निरंतरता ने निवेशकों को भरोसा बनाए रखा है।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई । भारतीय रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 28 पैसे की बढ़त के साथ ही 89.88 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, रिज़र्व बैंक के सीमित हस्तक्षेप और आयातकों द्वारा डॉलर की बढ़ती मांग रुपये पर लगातार दबाव बना रही है। शुक्रवार को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की घोषणा से पहले बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है, जिसका असर विनिमय दर पर दिखाई दे रहा है। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में सुबह कारोबार की शुरुआत रुपये ने 90.36 प्रति डॉलर पर की, लेकिन जल्द ही यह और कमजोर होकर 90.43 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को भी रुपया पहली बार 90 के पार बंद होकर 90.15 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर दर्ज हुआ था।

सोने के वायदा भाव में नरमी, चांदी में हल्की तेजी

- सोना 188 रुपए गिरकर 1,30,274, चांदी 269 रुपए तेज होकर 1,82,621 पर

नई दिल्ली । सोने-चांदी के वायदा बाजार में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत तेज रुख के साथ हुई, हालांकि सत्र के आगे बढ़ने के साथ सोने के भाव पर दबाव देखने को मिला। घरेलू मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का फरवरी वायदा कॉन्ट्रेक्ट 337 रुपये की मजबूती के साथ 1,30,799 प्रति 10 ग्राम पर खुला था, जबकि पिछले सत्र का बंद भाव 1,30,462 रुपए था। इस समय सोना 1,30,274 रुपए पर आ गया, जो शुरुआती स्तर से 188 रुपये की गिरावट दर्शाता है। दिन के दौरान इसने 1,30,799 रुपए का उच्च और 1,30,228 रुपए का निम्न स्तर छुआ। सोने ने इस वर्ष 1,31,699 रुपए का सर्वोच्च स्तर बनाया था। दूसरी ओर, चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रेक्ट 269 रुपये की तेजी के साथ 1,82,621 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 1,82,352 रुपये था। इस समय यह 2,45 रुपये की तेजी के साथ 1,82,597 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 1,82,697 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 1,82,021 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। चांदी के वायदा भाव ने इस साल 1,84,743 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मिले-जुले रुझान दिखाई दिए। कॉमेक्स पर सोना 4,234.50 डॉलर प्रति औंस पर खुलकर लगभग 4,223.10 डॉलर पर आ गया, जो लगभग 9.40 डॉलर की गिरावट दर्शाता है। इस वर्ष सोने का उच्चतम स्तर 4,398 डॉलर रहा है। वहीं चांदी 58.98 डॉलर प्रति औंस पर खुली और हल्की तेजी के साथ 58.81 डॉलर पर कारोबार कर रही थी। चांदी ने वर्ष का उच्च स्तर 59.61 डॉलर छुआ था।

भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 1.47 अरब डॉलर पहुंचा

- भारत के वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भी तेज़ी आई

नई दिल्ली ।

भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात अक्टूबर 2025 में तीन गुना से अधिक बढ़कर 1.47 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने यह केवल 46 करोड़ डॉलर था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में अमेरिका को कुल निर्यात 10.78 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 3.60 अरब डॉलर था। मासिक आधार पर निर्यात में उतार-चढ़ाव देखा गया। अप्रैल में यह 1.65 अरब डॉलर, मई में 2.29 अरब डॉलर था। जून में 1.99 अरब डॉलर, जुलाई में 1.52 अरब डॉलर, अगस्त में 96 करोड़ डॉलर और सितंबर में 88 करोड़ डॉलर तक गिर गया। अक्टूबर में निर्यात फिर बढ़कर 1.47 अरब डॉलर हुआ। अधिकारियों ने कहा कि शुल्क और नीति संबंधी अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात की गति कायम रही। भारत के वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भी तेज़ी आई है।

अप्रैल-अक्टूबर 2025 में यह 15.95 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 10.68 अरब डॉलर था। यह वृद्धि भारतीय स्मार्टफोन उद्योग की निर्यात क्षमता और अंतरराष्ट्रीय मांग को दर्शाती है।

रुपए की कमजोरी से महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका

- महंगाई बढ़ने से आरबीआई ब्याज दर बढ़ा सकता है

नई दिल्ली ।

डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का असर आम जनता की जेब पर सीधे पड़ रहा है। भारत कच्चे तेल, गैस और कई आवश्यक वस्तुओं का बड़ा आयातक है। डॉलर मजबूत होने से इनकी कीमत बढ़ती है। पेट्रोल-डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ती है, जो सब्ज़ी, दूध, अनाज और दैनिक उपयोग की चीज़ों की कीमतों में इजाफा करती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले पुर्ज़े विदेश से आते हैं। डॉलर मजबूत होने पर कंपनियों की लागत बढ़ती है और कीमतें बढ़ाना पड़ता है। आईटी और फार्मा कंपनियों को लाभ होता है, जबकि ऑटो, स्टील और इम्पोर्ट पर निर्भर सेक्टर दबाव में आते हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ता है, निवेशकों की चिंता बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से आरबीआई ब्याज दर बढ़ा सकता है। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ती है। विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए खर्च महंगा हो जाता है। रुपए की कमजोरी महंगाई, निवेश, बचत और रोजमर्रा की जीवनशैली पर व्यापक प्रभाव डालती है।

इंडिगो की उड़ानों पर संकटः तीन प्रमुख हवाई अड्डों से 180 से अधिक उड़ानें रद्द

- इंडिगो में अपनी उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त पायलट और चालक दल की कमी

मुंबई । गुरुग्राम स्थित घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से कुल 180 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं। मुंबई हवाई अड्डे से दिन भर में 86 उड़ानें (41 आगमन, 45 प्रस्थान), बेंगलुरु से 73 उड़ानें (41 आगमन सहित) और दिल्ली से 33 उड़ानें रद्द की गईं। सूत्रों के अनुसार दिन के आगे बढ़ने के साथ रद्द उड़ानों की संख्या और बढ़ सकती है, जिससे यात्रियों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इंडिगो अपनी उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त पायलट और चालक दल जुटाने में जूझ रही है। नए फ्लाइट ड्यूटी और विश्राम नियम (एफडीटीएल) लागू होने के बाद एयरलाइन को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इसी वजह से ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) गिरकर 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर 19.7 प्रतिशत रह गया, जो 2 दिसंबर के 35 प्रतिशत के आंकड़े से काफी कम है। पायलट संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने आरोप लगाया कि इंडिगो ने नई एफडीटीएल नियमों के लागू होने के बावजूद भर्ती पर रोक लगा रखी है। एफआईपी ने डीजीसीए से अनुरोध किया है कि एयरलाइन तब तक मौसमी उड़ान कार्यक्रम की मंजूरी न पाए जब तक पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध न हों। यदि इंडिगो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाती, तो अन्य

एयरलाइनों को स्लॉट आवंटन पर विचार करने की सिफारिश की गई है। डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में हुई रद्द और देरी की जांच शुरू कर दी है। एयरलाइन से कारण और सुधारात्मक योजना की जानकारी मांगी गई है।

आईआईटी प्लेसमेंट में उछाल, हेज फंड और ट्रेडिंग कंपनियों की भागीदारी बढ़ी

- आईआईटी कानपुर को पहले दिन अब तक के सबसे ज्यादा 672 ऑफर

नई दिल्ली ।

देश के प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में 1 दिसंबर से शुरू हुए प्लेसमेंट सीज़न में इस बार हेज फंड, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कंपनियों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार छात्रों को 90 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपये सालाना तक के आकर्षक पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित नई भूमिकाओं और उभरते क्षेत्रों के कारण कई आईआईटी इस साल नौकरी प्रोफाइल में विविधता लाने पर विशेष जोर दे रहे हैं, ताकि प्लेसमेंट केवल टेक कंपनियों और स्टार्टअप तक सीमित न रहे। आईआईटी रुड़की में पहले स्लॉट के दौरान डीई शॉ, दा विंची डेरिवेटिव्स, एनके सिक्योरिटीज रिसर्च और रूब्रिक जैसी प्रमुख ट्रेडिंग कंपनियों ने छात्रों को ऑफर दिए। इसके साथ ही अमेज़न, अमेरिकन एक्सप्रेस, एनवीडिया, क्वालकॉम, डेटाब्रिक्स, फ्लिपकार्ट, जोमैटो (इटरनल) और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी भर्ती प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। निवेश क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्क्वायरपॉइंट कैपिटल से भी ऑफर प्राप्त हुए हैं। आईआईटी के विभिन्न परिसरों को पहले दो दिनों में कुल 555 ऑफर मिले हैं, जिनमें कम से कम आठ अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। आईआईटी कानपुर ने इस साल रिकॉर्ड प्रदर्शन किया और पहले ही दिन 672 ऑफर हासिल किए। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। इनमें से नौ ऑफर विदेश से प्राप्त हुए हैं। संस्थान ने कहा कि कुछ परिणाम अभी लंबित हैं, इसलिए कुल ऑफरों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली, मुंबई, मद्रास, खड़गपुर और आईआईटी-बीएचयू जैसे पुराने एवं प्रतिष्ठित आईआईटी परिसरों में भी समान रुझान देखने को मिल रहा है। आईआईटी मद्रास में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और स्टार्टअप कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। हालांकि पैकेज की पुष्टि संस्थान ने नहीं की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऑफर 3 करोड़ रुपये तक पहुंच रहे हैं।

डॉलर बांड की मांग कमजोर! भारतीय कंपनियों का भरोसा अब रुपए पर

- इस साल डॉलर में कर्ज लेने से बच रही हैं भारतीय कंपनियां

नई दिल्ली ।

भारतीय कंपनियां इस साल डॉलर में कर्ज लेने से बच रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका में लगातार ऊंची चल रही ब्याज दरें और वैश्विक स्तर पर बढ़ता आर्थिक व भू-राजनीतिक तनाव। ऐसे माहौल में कंपनियों को रुपये में कर्ज लेना अपेक्षाकृत सुरक्षित और सस्ता लग रहा है। यही कारण है कि रुपये बॉन्ड ज़ार तेजी से बढ़ रहा है और 2025 में इसके नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक वे रिष्ठ अे धिकारी के अनुसार जब तक वैश्विक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जातीं और विदेशी ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, भारतीय कंपनियां रुपये-आधारित कर्ज को ही प्राथमिकता देंगी। बड़ी भारतीय कंपनियों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियां अब विदेशों की बजाय भारत के घरेलू बाज़ार से पूंजी जुटा रही हैं, क्योंकि यहां कर्ज उपलब्धता अधिक है और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव भी कम देखने को मिलता है। इस वर्ष अब तक 12.6 लाख करोड़ के रुपये बॉन्ड बिक चुके हैं, जबकि डॉलर में जारी बॉन्ड केवल 9 अरब डॉलर के रहे, जो पिछले साल की तुलना में 32 फीसदी कम है। इससे रुपये बॉन्ड मार्केट की मजबूती साफ दिखाई देती है। इसी रुझान को देखते हुए विदेशी बैंक भी भारतीय रुपये बॉन्ड बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में जुट गए हैं। हालांकि विदेशी बैंकों को एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे घरेलू दिग्गजों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। इनके पास मजबूत जमा आधार, विस्तृत शाखा नेटवर्क और सरकारी बैंकों को मिलने वाला सरकारी समर्थन उन्हें और अधिक प्रभावी बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी बैंक अब समझ चुके हैं कि भारत में रुपये-आधारित कर्ज ही आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारतीय बैंकों से सीधी टक्कर लेनी होगी।

फिच ने भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.4 फीसदी किया

- जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही

नई दिल्ली (ईएमएस)। साख रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.9 फीसदी से बढ़ाकर 7.4 फीसदी कर दिया है। एजेंसी ने वृद्धि का मुख्य कारण उपभोक्ता खर्च में तेजी, जीएसटी सुधार और बेहतर उपभोक्ता धारणा बताया। जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही, जो अप्रैल-जून तिमाही के 7.8 फीसदी से अधिक है। वित्त वर्ष की वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान निजी उपभोक्ता खर्च से है। मजबूत वास्तविक आय, सुधारित उपभोक्ता धारणा और हाल ही में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से खर्च बढ़ा है। लगभग 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई गईं, जिससे 99 प्रतिशत से अधिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हुई हैं। अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति केवल 0.3 फीसदी दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। फिच ने कहा कि घटती मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दिसंबर में मुख्य नीतिगत दर 5.25 फीसदी तक घटाने की संभावना देती है। आरबीआई ने इस साल अब तक रेपो दर में एक फीसदी कटौती की है। फिच का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी वृद्धि

6.4 फीसदी तक धीमी होगी। वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ अगले वर्ष की दूसरी छमाही में निजी निवेश में तेजी आने की उम्मीद है। एजेंसी का मानना है कि नीतिगत दर अगले दो साल तक 5.25 फीसदी पर स्थिर रहेगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ब्रिस्बेन टेस्ट : स्टार्क ने झटके 6 विकेट, जो रूट ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर ठोका अपना पहला शतक

ब्रिसबेन (एजेंसी)। जो रूट (नाबाद 135) शतकीय और जैक क्रॉली (76) रनों की अर्धशतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड ने एशेज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को दिन का खेल समाप्त होने के समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ विकेट पर 325 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रुट ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर अपना शतक सूखा समाप्त करते हुए 202 गेंदों पर नाबाद 135 रन में 15 चौके और एक छक्का लगाया। रुट का ओवरआल यह 40वां शतक है।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने जबरदस्त स्पेल किया, जबकि जो रूट ने शानदार शतक लगाया। ब्रिस्बेन की लाइट्स में आज के जमाने के दो महान खिलाड़ियों ने सबका ध्यान खींचा। स्टार्क पहली ही गेंद से लय में थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दो शुरुआती ब्रेकथ्रू देकर एकदम सही शुरुआत दी और जब भी इंग्लैंड संभलता हुआ लगा, उन्होंने फिर से स्ट्राइक किया। जब भी किसी पार्टनरशिप में मजबूती का इशारा मिला, उन्होंने उसे तोड़ने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लिया। हालांकि, रूट तूफान में शांति की तरह थे। जैसे-जैसे उनके आस-पास विकेट गिर रहे थे, उन्होंने एक शांत और ज़बरदस्त पारी खेलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला, और आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया; यह उस मौके के लिए एकदम सही था। क्रॉली के भरोसेमंद योगदान ने भी अपनी भूमिका निभाई, जैसा कि रूट और आर्चर की आखिरी विकेट की जोशीली साझेदारी ने किया, जिनकी तेज 61 रन की साझेदारी ने इंग्लैंड को पहले दिन 320 रन के पार पहुंचा दिया। पिंक-बॉल टेस्ट में इतने बड़े स्कोर के साथ, इंग्लैंड अगले फेज़ में असली मजबूत स्थिति में है। आज यहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने मात्र 5 रन के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। मिचेल स्टार्क ने बेन डकेट और ऑली पोप को आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये जो रूट ने जैक क्रॉली के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 117 रनों की साझेदारी हुई। 28वें ओवर में माइकल नीसर ने जैक क्रॉली को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। जैक क्रॉली ने 93 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 76 रन बनाये। हैरी ब्रूक (31), कप्तान बेन स्टोक्स और विल जैक्स 19-19 बनाकर आउट हुए।

इसी दौरान 66वें ओवर में बोलैंड की गेंद पर चौका लगाकर जो रूट ने अपना शतक पूरा किया। जो रूट का यह 40वां टेस्ट शतक है। इसी के साथ रूट, लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन शतक बनाने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उनके लंबे समय से चला आ रहा शतक सूखा भी समाप्त हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने नौ अर्धशतक लगाए थे, लेकिन शतक तक पहुंचने में असफल रहे थे। गस ऐटकिंसन (चार) और ब्राइडन कार्स (शून्य) को मिचेल स्टार्क ने 67वें ओवर में आउट किया। दिन का खेल समाप्त होने के समय इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बना लिए थे और (जो रूट नाबाद 135) और जोफ्रा आर्चर (नाबाद 32) क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट लिए। माइकल नीसर और स्कॉट बोलैंड ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

बीसीसीसीआई की नाराजगी को देखते हुए विजय हजार ट्रॉफी में खेलने को तैयार हुए विराट

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा है कि वह दिल्ली की ओर से आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को तैयार है। माना जा रहा है कि विराट ने ये फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के दबाव में लिया है। इसका कारण है कि बोर्ड पहले एकदिवसीय के बाद उनके दिये बयान से नाराज था जिसको देखते हुए विराट को 15 साल के बाद इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है।वहीं पहले वह इसमें खेलने को तैयार नहीं थे। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई विराट के सार्वजनिक रुप से दिखे उस बयान से नाराज थी। उसके बाद ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला किया।विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की टीम अपना पहला मुकाबला 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलेगी।

कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही एकदिवसीय में 135 रनों की मैच विजेता पारी खेलने के बाद कहा था कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा तैयारी में भरोसा नहीं करता। मेरा पूरा क्रिकेट मानसिक है। जब तक मैं मानसिक रूप से मजबूत महसूस करता हूं तो मैं खेल सकता हूं। उन्होंने कहा, 'मैंने 300 एकदिवसीय मैच खेल खेले हैं और 15-16 साल में काफी अधिक क्रिकेट खेला है। इसको देखते हुए मेरा मानना है कि अगर आप नेट में बिना कोई ब्रेक लिए डेढ़, दो घंटे खेल सकते हैं तब आप हर जरूरत को पूरी कर रहे हैं।'कोहली के इसी बयान से बीसीसीआई भड़की हुई थी। उसने इससे पहले इन दोनो को घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी थी ताकि ये दोनो भारत की ओर से एकदिवसीय प्रारुप खेलने के लिए तैयार रहें। वहीं रोहित ने पहले ही कहा दिया था कि वह मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए लिए तैयार हैं।

जडेजा की धीमी बल्लेबाजी से हारे : इरफान पठान

रायपुर (एजेंसी)। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि दूसरे एकदिवसीय में भारतीय टीम की हार का कारण अनुभवी बल्लेबाज रविन्द्र जडेजा की धीमी बल्लेबाजी रही है।

भारतीय टीम ने इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य दिया था पर इसके बाद भी वह इसे बचा नहीं पायी। पठान ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका ने 39 से 49 ओवरों के बीच कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे भारतीय टीम 370 तक नहीं पहुंच पायी। इरफान के अनुसार 15 से 20 रन और बनते तो शायद परिणाम अलग होता। उन्होंने कहा कि जडेजा ने धीमी बल्लेबाजी की है। जडेजा ने सातवें नंबर पर आने के बाद 27 गेंदों में केवल 24 रन बनाए। उन्होंने कप्तान केएल राहुल के साथ छठे विकेट के लिए 54 गेंदों में 69 रन बनाये थे।

इरफान ने कहा, राहुल ने अच्छा फिनिश किया। उन्होंने एक और कप्तानी पारी खेली। उनका अच्छा फिनिश करना जरूरी थी, अगर वो नहीं होता तो इतने रन भी भारत के नहीं बनते। मेरे हिसाब से जो जडेजा की पारी ठीक नहीं थी। उन्होंने 27 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाए। भारतीय टीम के अधिकतर बल्लेबाजों ने 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा बनाये पर जडेजा ने 88 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। जिस प्रकार के वह बल्लेबाज हैं उसमें ये आंकड़ा सही नहीं है। जडेजा का रवैया आक्रामक नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने शुरु में संभलकर खेलने के बाद आक्रामक रुख दिखाया। दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में ही 359 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका की ओर से एडेन मार्करम ने 110 जबकि मैथ्यू ब्रीट्जके ने 68 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 54 रन बनाये।

हार्दिक पांड्या का भारी क्रेज, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच का वेन्यू बदला गया

बड़ौदा बनाम गुजरात मैच फैंस की भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शिफ्ट

हैदराबाद (एजेंसी)। मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान एक अभूतपूर्व फैसले में बड़ौदा बनाम गुजरात का मुकाबला भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ती जरूरत के चलते राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। यह फैसला हार्दिक पांड्या के प्रति उमड़ रही असाधारण फैन-फॉलोइंग के चलते लिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, टीम होटल, अभ्यास स्थल और टिकट काउंटरों के बाहर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ देखी गई जो सामान्य घरेलू मैचों की तुलना में कई गुना अधिक थी। आयोजकों का मानना है कि यह भीड़ पूरी तरह हार्दिक पांड्या को देखने की दीवानगी के कारण उमड़ी। एक वरिष्ठ आयोजक ने बताया, 'हार्दिक पांड्या के प्रति उत्साह अविश्वसनीय है। फैन टर्नआउट, पूछताछ और भीड़ का दबाव हमारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा था। सुरक्षित और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मैच को राजीव गांधी स्टेडियम में स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया।' राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो अंतरराष्ट्रीय मैचों और IPL मुकाबलों की मेजबानी के लिए जाना जाता है, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और उच्च क्षमता के कारण इस अप्रत्याशित भीड़ को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प माना गया।हैदराबाद में पिछले दो दिनों में IPL जैसी हलचल देखी गई प्रशंसक अभ्यास सत्रों के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, पोस्टर-बैनर लेकर घूम रहे हैं, टिकट के लिए लाइनें लगा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह जता रहे हैं यह सब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी को लेकर है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुकाबले के बारे में

बड़ौदा बनाम गुजरात मैच भारत की प्रमुख घरेलू टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का हिस्सा है और वेन्यू बदलने के बाद अब इसके रिकॉर्ड भीड़ जुटाने की उम्मीद है।

अश्विन बोले, इस बार ग्रीन पर आईपीएल नीलामी में लग सकती है सबसे बड़ी बोली

मुम्बई । स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि 16 दिसंबर को आबूधाबी में 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र के लिए होने वाली नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर सबसे अधिक बोली लग सकती है ।ग्रीन फिट नहीं होने के कारण पिछले साल आईपीएल से बाहर थे। अश्विन के अनुसार आंद्रे रस्सेल और ग्लेन मैक्सवेल के सन्यास के कारण ग्रीन ही अब सबसे बेहतर विदेशी ऑलरांउर के तौर पर उलब्ध हैं, ऐसे में उनकी मांग बढ़ना तय है। अश्विन के अनुसार सभी फ्रेंचाइजियां ऐसे खिलाड़ी को लेना चाहेंगी जो तेज गेंदबाजी के साथ ही मध्य क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी कर सके और ये सभी खूबियां ग्रीन में हैं। अश्विन ने कहा, ग्रीन के अलावा इस बार उनके साथी खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन के पास भी मोटी रकम हासिल करने का अवसर है। ग्रीन इस समय विश्व के बेहतरीन टी20 खिलाड़ियों में शामि हैं।एक अच्छे आक्रामक बल्लेबाज होने के साथ ही वह 140 से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। उनके प्रदर्शन में निरंतरता बनी रहती है।ग्रीन ने 40 से अधिक के औसत और तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।इस ऑलराउंडर ने अब तक दो सही सत्र खेले हैं और 29 मैचों में 707 रन बनाये हैं इसके अलावा 16 विकेट लेकर दिखाया है कि वह एक मैच विजेता हैं।ग्रीन ने दबाव के बीच ही मैच विजेता पारियां खेली हैं।

अपने गेंदबाजी कौशल को निखारने मोर्कल और अर्शदीप से सलाह ले रहे हर्षित राणा

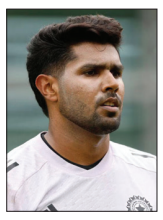

मुम्बई ।युवा तेज तेज गेंदबाज हर्षित राणा भारतीय टीम में आने के बाद से ही टीम में अपनी जगह पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। हर्षित का सकारात्मक पक्ष ये है कि वह गेंदबाजी के साथ ही अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं हालांकि वह इस बार के लिए निशाने पर रहते हैं कि मुख्य कोच गंभीर का करीबी होने से उन्हे खेलने के अवसर मिल रहे हैं। वहीं इन आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देते हुए हर्षित नई गेंद से अपने कौशल को सुधारने के लिए गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ काम कर रहे हैं। हर्षित ने कहा, ''नई गेंद से मैं मोर्ने (मोर्कल) के साथ बहुत अभ्यास कर रहा हूं और मैं अर्शदीप से बहुत बात करता रहता हूं। मुझे लगता है कि अर्शदीप के पास बहुत अनुभव है और वह अभ्यास के दौरान मेरी मदद और मार्गदर्शन करते रहते हैं।' पारी के 34वें ओवर के बाद एक गेंद के नियम को लेकर हर्षित ने कहा कि भारतीय टीम इस बात पर नजर रखती है कि दोनों गेंदों में से कौन सी गेंद अधिक पुरानी हो रही है जिससे कि उसे चुना जा सके। उन्होंने कहा, ''आजकल के क्रिकेट में गेंदबाज को इतनी मदद नहीं मिलती इसलिए यह नियम हमारे लिए बहुत सहायक है और यह हमेशा दिमाग में रहता है कि कौन सी गेंद पुरानी हो रही है। और हर कोई उस गेंद को चुनने में शामिल होता है।'' हर्षित ने कहा कि अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम में रहने से भी उनको काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा, ''यह मेरे लिए और जाहिर है कि पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर ऐसे अनुभवी खिलाड़ी मैदान और ड्रेसिंग रूम में आपके साथ रहते हैं तो टीम का माहौल बहुत अच्छा होता है। यहां तक कि अगर आप ड्रेसिंग रूम में हैं तो यह पूरी टीम के लिए एक खुशी का माहौल है।''

2026 फीफा विश्वकप के सफल आयोजन के लिए प्रयास कर रहे : गिउलिआनी

वाशिंगटन (एजेंसी)। 2026 फीफा वर्ल्ड कप को लेकर अमेरिका में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। विश्व कप के लिए बनाये गये व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के कार्यकारी निदेशक एंड्रयू गिउलिआनी ने कहा है कि ये विश्वकप सबसे सुरक्षित और यादगार रहेगा। गिउलिआनी के अनुसार इसके लिए सभी प्रकार के इंतजाम किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अमेरिका फुटबॉल के इस सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें आने वाले लाखों प्रशंसकों को एक सुरक्षित और आरामदेह माहौल उपलबध कराया जाएगा। गिउलिआनी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए निर्देश दिये हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित किया जाये कि देश में एक सुरक्षित, स्वागत योग्य और यादगार विश्व कप का आयोजन हो। 2026 के टूर्नामेंट को लेकर गिउलिआनी ने कहा कि विश्व कप अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के साथ ही होगा, जिसमें 4 जुलाई, 2026 को फिलाडेल्फिया में एक मैच होना है। उन्होंने कहा, यह हमें अमेरिका का सबसे अच्छा रूप दिखाने का अवसर देता है, जिसमें हमारी मेहमाननवाजी और हमारा इनोवेशन तो है ही, साथ ही ये उस अमेरिकी भावना को भी दिखाता है जिस पर हमें बहुत गर्व है।

गिउलिआनी ने कहा कि विश्व कप में 48 देश, 104 मैच 49 टीम बेस कैंप और लाखों अंतरराष्ट्रीय मेहमान शामिल होंगे। इससे पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थानीय व्यवसायों और 11 अमेरिकी मेजबान शहरों को फायदा होगा। यह एकता का एक वैश्विक क्षण रहेगा। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा है।

राहुल ने टॉस को बताया हार के लिए जिम्मेदार, ओस के कारण गेंदबाजी थी मुश्किल

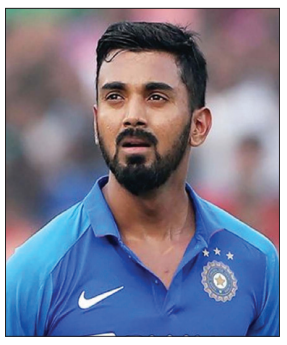

रायपुर ।भारतीय क्रिकेट टीम की मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे एकदिवसीय में 358 रन बनाने के बाद हुई हार के लिए कप्तान के एल राहुल ने टॉस हारने को कारण बताया है। राहुल ने कहा , इस परिणाम को पचाना ज्यादा कठिन नहीं हैं क्योंकि रात के समय काफी ओस रहती है जिससे गेंदबाजी में काफी परेशानी आती है। अंपायरों ने कई बार गेंद बदली जिसके बाद भी गेंदबाजी आसान नहीं थी। मैं लगातार दो टॉस हारने पर निराश हूं हालांक कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम बेहतर कर सकते थे पर कर नहीं पाये। मुझे पता है कि 350 अच्छा स्कोर लगता है हालांकि पिछले मैच के बाद भी ड्रेसिंग रूम में यही हो रही थी कि किस प्रकार हम 20 से 25 रन कैसे और बना सकते थे जिससे गेंदबाजों को गीली गेंद से गेंदबाजी करते समय स्कोर का बचाव करने में आसानी हो। गेंदबाजों ने पूरा प्रयास किया लेकिन इसके बाद भी सुधार की जरुरत है। हमने मैदान में कुछ आसान रन भी दिए जो भारी पड़ गये। अगर हम गेम के तीनों पहलुओं को देखें तो थोड़े और बेहतर हो सकते थे। शायद उन 20–25 रनों से हमें लाभ होता। राहुल ने ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा, ऋतुराज को बल्लेबाजी करते हुए देखना काफी अच्छा अनुभव था। विराट को हमने 53 बार ऐसा करते देखा है। वह अपना काम करते रहते हैं, हमें यह देखने की आदत है। वहीं ऋतुराज जिस तरह से बल्लेबाजी की। उसकी जितनी तारीफ करें कम है। उसने स्पिनरों का बेहतर तरीके से सामना किया और फील्डरों के बीच में से गेंद निकाली। उसने अर्धशतक बनाने के बाद जबरदस्त तेजी दिखायी और उसी से हमें 20 रन ज्यादा मिले। अगर निचला क्रम और रन बनाता तो हम और बेहतर हालत में होते। राहुल ने अपने बल्लेबाजी क्रम पर कहा, आज पहली बार मुझे छह नंबर पर रखा गया हालांकि मैं नंबर–5 पर बल्लेबाजी करने आया।

जीत के बाद बोले बावुमा, भारतीय टीम के खिलाफ खेलना बेहद कठिन

रायपुर (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तैंबू बावुमा ने भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय में मिली रिकार्ड जीत पर खुशी जतायी है।

बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय में 359 रनों के कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर लिया। यह एकदिवसीय में लक्ष्य का पीछा करते हुए विदेशी धरती पर किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है।

बावुमा ने दूसरा एकदिवसीय चार विकेट से जीतने के बाद कहा, मुझे खुशी है कि हमने जीत की दहलीज पार कर ली। इस मैच में आते हुए हमारा ध्यान था कि गेंदबाजी कैसे बेहतर की जा सके। वहीं बल्लेबाजी में शीर्ष क्रम ने अच्छा प्रदर्शन किया। एडेन मार्करम और मैथ्यू ब्रीटजके के अलावा कॉर्बिन बॉश ने भी अच्छा खेल दिखाया है। फिनिशिंग भी अच्छी रही। यह प्रकार से ये कठिन लक्ष्य हासिल किया गया। उससे साफ है कि भारतीय टीम के खिलाफ खेलना कितना मुश्किल है। हमें आगे भी इसी प्रकार के प्रदर्शन की जरुरत होगी। जब मैं क्रीज पर आया तो एडेन गेंद को खेल रहा था। मैं उसके साथ साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहा था। कप्तान ने साथ ही कहा, इस मैच से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला है। एक अच्छी सीरीज तैयार हुई है। मुझे लगता है कि जो लोग यहां हैं, वे हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं। हर स्थान के लिए कड़ी टक्कर थी। इसलिए मुझे लगता है कि बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। यह स्थिति गेंदबाजों के साथ भी है। इस तरह के प्रदर्शन से मनोबल बढ़ता है।

बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में होगी भारत की असली परीक्षा

चेन्नई (एजेंसी)। भारत ने अपेक्षाकृत आसान पूल में लगभग प्रत्येक विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन स्न्ह्वा पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में उसकी असली परीक्षा बेल्जियम के खिलाफ शुक्रवार को यहां होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच में होगी।

चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड के साथ पूल बी में शामिल भारत ने शानदार प्रदर्शन करके पहले स्थान पर रहते हुए नाकआउट दौर में प्रवेश किया। भारतीय टीम ने पूल चरण में 29 गोल किए और एक भी गोल नहीं खाया, जो टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी 24 टीमों में सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट है। लेकिन पीआर श्रीजेश की कोचिंग वाली टीम यह बात अच्छी तरह जानती है कि इन परिणामों का आगे कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि टूर्नामेंट के अंतिम चरण में उनका सामना मजबूत टीमों से होगा।

यहां से कोई भी चूक भारत के 9 साल बाद घरेलू मैदान पर खिताब जीतने के सपने को चकनाचूर कर सकती है। भारत ने आखिरी बार 2016 में लखनऊ में खिताब जीता था। भारत पूल चरण में शानदार प्रदर्शन करके इस उपलब्धि को दोहराने की स्थिति में दिख रहा है। उसने अभी तक 18 मैदानी गोल किए हैं। इसके अलावा उसने नौ गोल पेनल्टी कॉर्नर से और दो पेनल्टी स्ट्रोक से किए हैं। लेकिन यहां से भारतीय टीम की राह आसान नहीं होगी और किसी भी तरह का अति आत्मविश्वास उसे खिताब की दौड़ से बाहर कर सकता है।

चिली और ओमान के खिलाफ पहले दो मैचों में भारत ने दबदबा बनाए रखा और मनचाहे गोल दागे। उसने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराया, लेकिन स्विस टीम ने भारत की रक्षापंक्ति के सामने कड़ी चुनौती पेश की। इस मैच में गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह और बिक्रमजीत सिंह ने कुछ शानदार बचाव किए। पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करना अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले मैच में शिलानंद लाकड़ा ने दो बार पेनल्टी कार्नर को गोल में बदला लेकिन भारत कप्तान रोहित और अनमोल एक्का से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगा।

भारतीय स्ट्राइकरों ने पूल चरण में शानदार प्रदर्शन किया। दिलराज सिंह (06 गोल), मनमीत (05), अर्शदीप सिंह (04), अजीत यादव और गुरजोत सिंह (दोनों दो-दो गोल) सभी ने अपना प्रभाव छोड़ा है। रोसन कुजूर, एड्रोई एक्का, अंकित पाल और इंगलेम्बा लुवांग थोउनाओजम ने मध्यपंक्ति में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन उनकी असली परीक्षा अब होगी। श्रीजेश भी पूल चरण के प्रदर्शन को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं।

उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। अगले मैच से असली टूर्नामेंट शुरू होगा और हमारे लिए उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है।% बेल्जियम अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा लेकिन भारत को उसे किसी भी तरह से हल्के से लेने की गलती नहीं करनी होगी। बेल्जियम ने अभी तक टूर्नामेंट में 22 गोल किए हैं और वह सर्वाधिक गोल करने वाली टीमों में तीसरे नंबर पर है। उसने 11 मैदानी गोल किए जबकि इतने ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला।

श्रीजीश ने कहा, 'जूनियर विश्व कप कोई आसान टूर्नामेंट नहीं है। मेरा मतलब है कि इनमें से कोई भी टीम आपको आसानी से जीत हासिल नहीं करने देगी। टूर्नामेंट की असली शुरुआत तो अब होगी और कोई भी गलती भारी पड़ सकती है।% क्वार्टर फाइनल के अन्य मैचों में स्पेन का सामना न्यूजीलैंड से, फ्रांस का सामना जर्मनी से और नीदरलैंड का सामना अर्जेंटीना से होगा।

रोहित, विराट पर घरेलू क्रिकेट खेलने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिये : एमएस के प्रसाद

मुम्बई ।चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एमएस के प्रसाद ने कहा है कि अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर घरेलू क्रिकेट खेलने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिये।प्रसाद ने ये बात भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को उसे निर्देश को लेकर कही है जिसमें बोर्ड ने केन्द्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का अनिवार्य बनाया है। केवल फिट नहीं होने पर ही खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट से बाहर रहने की अनुमति दी गयी है। ऐसे में माना जा रहा है कि विराट और रोहित आने वाले समय में विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलते हुए दिख सकते हैं। वहीं प्रसाद का मानना है कि बोर्ड को इन सीनियर खिलाड़ियों पर घरेलू मैच खेलने का दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित और कोहली न सिर्फ टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं बल्कि युवा खिलाड़ियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बोर्ड का मानना है सभी अनुबंधित खिलाड़ी अवसर मिलने पर घरेलू क्रिकेट खेलें, जिससे उनकी फिटनेस के साथ ही लय भी बनी रहेगी। इसी के बाद दिल्ली जिला क्रिकेट संघ ने कहा था कि विराट आगामी विजय हज़ारे ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उसने रोहित के भी मुम्बई की ओर से मैदान पर उतरने की उम्मीद जतायी। इस नियम का उद्देश्य घरेलू स्तर पर स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी बढ़ाना है, जिससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा और अनुभव मिल सके।वहीं प्रसाद ने वर्तमान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को आगाह किया है कि कोहली और रोहित जैसे बड़े खिलाड़ियों पर घरेलू क्रिकेट खेलने का दबाव न बनाया जाए। साथ ही कहा कि इससे उनपर मानसिक दबाव पड़ेगा। रेलू क्रिकेट खेलना अच्छा है, लेकिन इसे जबरदस्ती की तरह पेश नहीं करना चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

खालिदा को देखने ब्रिटेन की टीम बांग्लादेश रवाना

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन से चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम वेंटिलेटर पर रखी गई पूर्व पीएम खालिदा जिया के इलाज का आकलन करने बांग्लादेश का दौरा करेगी। खालिदा जिया की हालत यहां एक निजी अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। एवरकेयर अस्पताल के जाहिद हुसैन ने कहा, ब्रिटेन के विशेषज्ञ जांच के लिए निकल चुके हैं।

तुर्किये तट के पास रूसी तेल टैंकर पर हमला, चालक दल सुरक्षित

मास्को, एजेंसी। रूस से जॉर्जिया जा रहे रूसी तेल टैंकर एमआईडीवीओएलजीए-2 ने तुर्किये तट से 80 मील दूर 13 सदस्यीय दल पर हमला किया गया। हालांकि हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुर्किये की समुद्री प्राधिकरण बताया कि जहाज ने सहायता नहीं मांगी और सिनोप बंदरगाह की ओर बढ़ता रहा। यह घटना ऐसे समय आई है जब पिछले सप्ताह यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने काला सागर में दो रूसी-गामी टैंकरों को निशाना बनाया था।

स्टारबक्स ने हड़ताली कर्मियों को दिए 31.33 करोड़ रुपये

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी कंपनी स्टारबक्स न्यूयॉर्क में हड़ताल के बीच अपने 15,000 से अधिक कर्मचारियों को लगभग 31.33 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने उन्हें स्थिर शेड्यूल नहीं दिए और मनमाने ढंग से काम के घंटे घटाए। कंपनी के चेयरमैन और सीईओ ब्रायन निकोल निकोल ने इससे पहले कहा था कि कंपनी की संरचना को सुधारने का उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है और उन सिलोस को खत्म करना है जो संचार को धीमा करते हैं।

अमेरिका में जिम्नास्टिक कोच पर यौन शोषण के आरोप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के आयोवा में एक जिम्नास्ट कोच पर यौन शोषण को लेकर कार्रवाई न करने पर यूएसए जिम्नास्टिक और यूएस सेंटर फॉर सेफपोर्ट नामक संस्था के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार 2017 में उन्होंने कोच के उन्हें अनुचित तरीके से छूने की जानकारी संस्थाओं को दी गई थी। लेकिन उन्होंने न तो मामले में पड़ताल करना जरूरी समझा और न ही कोई कार्रवाई। इसके चलते कोच को 2018 में आयोवा के एक अन्य जिम में नौकरी मिली। वहां भी वह बेखौफ होकर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता रहा।

नेपाल : मधेश प्रदेश सभा की बैठक तत्काल बुलाने की मांग

काठमांडू, एजेंसी। मधेश राज्य सरकार में विपक्षी दलों के गठबंधन ने प्रदेश सभा की बैठक तुरंत बुलाने की मांग की है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सरोजकुमार यादव को 24 घंटे में विश्वास का मत हासिल करने का आदेश दिया है। इसी के चलते गठबंधन में शामिल दलों ने प्रदेश सभा की बैठक का आग्रह किया। सीएम विश्वास मत नहीं लेते हैं या बहुमत जुटाने में नाकाम रहते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 168 (2) के तहत नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अदालती आदेश जारी होने के अगले ही दिन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केंद्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सहित विपक्षी दलों ने उप सभामुख बबीता राउत से प्रदेश सभा की बैठक शाम 4 बजे बुलाने का अनुरोध किया। उच्च सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दलों ने अपने सांसदों को जिले से बाहर न जाने का निर्देश भी दिया है।

उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में टीटीपी के 7 आतंकवादी ढेर

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग अभियानों में सात टीटीपी आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, दोनों ऑपरेशन उत्तरी वजीरिस्तान जिले में किए गए। सुरक्षा बलों द्वारा मीर अली तहसील में एक खुफिया-आधारित अभियान (आईबीओ) चलाया गया, जिसके दौरान छह आतंकवादी मारे गए। आईएसपीआर ने बताया कि जिले के स्पिनवाम क्षेत्र में आईबीओ में एक अन्य आतंकवादी मारा गया। बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों से हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया है, जो सुरक्षा बलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियों और निर्दोष नागरिकों की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

ट्रम्प के दामाद के साथ पुतिन की 5 घंटे बैठक

रूसी राष्ट्रपति बोले- डोनबास लिए बिना कोई शांति नहीं, जंग रोकने पर फैसला नहीं

मॉस्को, एजेंसी। रूस में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रम्प के दामाद जैरेड कुशनर के बीच मंगलवार को यूक्रेन युद्ध को लेकर पांच घंटे बैठक हुई। इतनी लंबी बैठक के बाद भी दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर यूरी उशाकोव ने कहा कि बातचीत फायदेमंद रही, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव सामने नहीं आया जिस पर सहमति बन सके। पुतिन का साफ कहना है जब तक यूक्रेन, रूस को डोनबास का इलाका नहीं सौंपेगा कोई समझौता नहीं होगा। उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव के कुछ हिस्सों से सहमति जताई, लेकिन कई बातों पर साफ तौर पर नापसंदगी दिखाई। उनके मुताबिक अभी कई मुद्दों पर और काम करना होगा।

पुतिन-ट्रम्प की बैठक तय नहीं : उशाकोव ने यह भी कहा कि फिलहाल पुतिन और ट्रम्प की कोई नई बैठक तय नहीं है और आगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि शांति योजना पर कितना डेवलपमेंट होता है। जब ये बातचीत चल रही थी, उसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ओर से मिलने वाले इशारे का इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी बातचीत के बाद सीधे यूक्रेन को बताएंगे कि बैठक में क्या हुआ और उसके बाद ही यूक्रेन अपना अगला कदम तय करेगा। यूक्रेन के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि पुतिन का रुख कैसा रहेगा। वे कुछ बातों पर कुछ बातों पर सहमति और कुछ पर सख्त आपत्ति जताएंगे। अब असली सवाल यह है कि अमेरिका इस पर कैसे रिस्पांस करता है।

पुतिन ने कहा था- हम युद्ध नहीं चाहते : इस बैठक से ठीक पहले पुतिन ने यूरोप पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका की शांति योजना में ऐसे बदलाव कर रहा है जिससे बातचीत आगे न बढ़ सके। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप लड़ाई शुरू करना चाहता है, तो रूस तैयार है। उधर, व्हाइट हाउस ने बैठक से पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत से कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में यूक्रेनी प्रतिनिधियों से फ्लोरिडा में मुलाकात की थी, जहां शांति योजना में कई बदलावों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मौजूदा शांति योजना पहले की 28 बिंदुओं वाली योजना में सुधार करके बनाई गई है, क्योंकि पुरानी योजना को यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने रूस के पक्ष में बताया था।

जेलेंस्की बोले- हर तरह की डिप्लोमेटिक कोशिशें करेंगे : जेलेंस्की इस समय यूरोपीय देशों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और आयरलैंड पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन किसी भी कूटनीतिक प्रयास को बेहद गंभीरता से ले रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि एक मजबूत शांति और सुरक्षा गारंटी मिले।

उन्होंने यह भी कहा कि रूस शांति से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि दूसरे देशों को प्रभावित किया जा सके। विटकॉफ और पुतिन के बीच यह इस साल की छठी बैठक थी। इतनी कोशिशों के बावजूद अब तक कोई ठोस समझौता नहीं बन सका है। अमेरिका और यूक्रेन को उम्मीद है कि बातचीत आगे बढ़ेगी, जबकि पुतिन लगातार इस बात पर अड़े हैं कि यूक्रेन को उन इलाकों से पीछे हटना होगा जिन्हें रूस अपना हिस्सा मानता है।

अमेरिका में दो लोगों की मौत के मामले में भारतीय व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का आरोप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एक ट्रक से टक्कर के बाद कार में सवार दो लोगों की मौत के मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए हैं। राजिंदर कुमार (32) पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के कारण किसी की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है।

हादसे में कार में सवार विलियम मिका कार्टर (25) और जेनिफर लिन लोवर (24) की मौत हो गई थी। जिस ट्रक से उनकी टक्कर हुई थी, उसे कुमार ही चला रहा था। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचसी) ने कहा कि आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने कुमार की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है।

ओरेगन राज्य की पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारियों को 24 नवंबर की रात डेशूट्स काउंटी में दो वाहनों की टक्कर की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुमार का ट्रक सड़क के बीचोंबीच खड़ा था, जिसकी वजह से दोनों ओर से आवाजाही बंद हो गई थी। उसी दौरान राजमार्ग पर तेज रफ्तार में आ रही कार्टर की कार ट्रक से टकरा गई थी।

कार्टर और लोवर को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था जबकि कुमार को कोई चोट नहीं लगी थी। इसके बाद कुमार को गिरफ्तार करके डेशूट्स काउंटी जेल भेज दिया गया था। डीएचएस के अनुसार कुमार भारत से आया अवैध प्रवासी है और वह 28 नवंबर 2022 को अरिजोन के ल्यूकविल के पास गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था।

लंदन में 'मेगा' दूतावास बनाने की चीन की योजना में और देरी

लंदन, एजेंसी। मध्य लंदन में चीन के एक विशाल दूतावास के निर्माण की विवादास्पद योजना पर एक लंबे समय से लंबित निर्णय को एक बार फिर टाल दिया गया है। अधिकारियों ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर यह जानकारी दी है। लंदन के वित्तीय जिले और संवेदनशील डेटा केबलों के करीब एक बहुत बड़ी साइट पर बनने वाले इस 'मेगा दूतावास' की योजना वर्षों से रुकी हुई है। आलोचकों ने चिंता जताई है कि इस इमारत का इस्तेमाल जासूसी के अड्डे के रूप में किया जाएगा, और राजनीतिक गलियारों के सांसदों ने सरकार से इस प्रस्ताव को खारिज करने का आग्रह किया है। अधिकारियों को 10 दिसंबर तक दूतावास पर निर्णय लेना था, लेकिन प्लानिंग इंस्पेक्टरेट ने कहा कि इस पर पूरी तरह से विचार करने के लिए अधिक समय देने हेतु समय सीमा को बढ़ाकर 20 जनवरी कर दिया गया है। प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर के प्रवक्ता टॉम वेल्स ने पत्रकारों से कहा, 'गृह कार्यालय और विदेश कार्यालय ने विशेष सुरक्षा निहितार्थों पर विचार दिए हैं, और शुरू से ही यह स्पष्ट किया है कि जब तक हम यह पुष्टि नहीं कर देते कि उन विचारों को पूरा या सुलझा लिया गया है, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।' यह देरी हाल के हफ्तों में चीनी जासूसी के कई आरोपों से निपटने को लेकर ब्रिटिश सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच हुई है।

कैलिफोर्निया में 2006 के बाद 2025 में कम हुए नरसंहार : **कैलिफोर्निया, एजेंसी।** अमेरिका के कैलिफोर्निया में साल 2006 के बाद नरसंहार के मामले 2025 में सबसे कम रहे। कैलिफोर्निया में बच्चों की जन्मदिन पार्टी में हुई हालिया गोलीबारी में चार लोगों की मौत हुई थी। ये इस साल की 17वां नरसंहार था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कमी स्थायी सुरक्षा का संकेत नहीं, बल्कि औसत स्तर पर लौटने जैसा है। क्रिमिनोलॉजिस्ट जेम्स ऐलन फॉक्स के अनुसार, 2025 में सामूहिक हत्याएं 2024 की तुलना में 24 फीसदी कम रहीं।

पश्तून सांसद की खरी-खरी, कहा- एक गांव भी बिना सिस्टम के नहीं चलता, यहां पूरा पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा

इस्लामाबाद, एजेंसी। खैबर पख्तूनख्वा के मुद्दों को पाकिस्तानी संसद में बेबाकी से उठाने वाले सांसद महमूद खान अचाकजई ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सेना एवं सरकार की ओर से अत्याचारों का विरोध किया है और कहा कि यहां तो पूरा देश ही मनमर्जी से चल रहा है। अचाकजई ने कहा कि पाकिस्तान में संविधान और व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। इस देश में संविधान अब एक औपचारिकता मात्र है। उन्होंने मंगलवार को पश्तून नायक खान अब्दुल समद खान की 52वीं बरसी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरकार पर खैबर पख्तूनख्वा की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान ने कहा कि इस देश में संविधान अब एक औपचारिकता मात्र रह गया है। आखिर कोई देश कैसे बिना किसी नियम और कानून के चल सकता है। एक गांव भी इस तरह नहीं चल सकता, लेकिन यहां तो पूरा पाकिस्तान ऐसे ही चलाया जा रहा है। यही नहीं उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुराए हुए जनादेश से बहुमत तैयार कर लिया गया। संसद बन गई। पैसे और प्रभाव से संविधान को खत्म करने और व्यवस्था को कमजोर करने को अनुमति नहीं दी जा सकती। यही नहीं उन्होंने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि संसद में बहुमत हासिल करने के लिए पीटीआई के लोगों पर अत्याचार किए गए। उन्होंने कहा कि हजारों घरों में रेड मारी गई। पुलिस थानों में कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया गया। वहां डिटेंशन सेंटर बना दिए गए। यहां तक कि उनकी गरिमा का भी उल्लंघन हुआ। इसके बाद भी पब्लिक ने पीटीआई को ही जनादेश दिया, लेकिन जब वोटों की गिनती हो रही थी तो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहे लोगों को विजेता घोषित कर दिया गया।

कुछ लोगों को लाखों रुपये ले-देकर विजेता बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी जब बहुमत मिलता नहीं दिखा तो अदालतों से फैसले दिलाकर कई लोगों को अयोग्य ही घोषित करा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में अदालतें कोई सही फैसला नहीं दे सकतीं। वे बिना दबाव के निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं।

वेनेजुएला पर अमेरिका सख्त: ट्रंप ने चेताया- अब जमीन पर भी होंगे हमले, कैरिबियन सागर में हमलों के बाद बढ़ा तनाव

वॉशिंगटन, एजेंसी। कैरिबियन सागर में कथित वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की नौकाओं पर अमेरिकी हमलों के बाद अब तनाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कारण है कि कैबिनेट बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक चेतावनी दी है कि सागर में हमले के बाद अब अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला के अंदर भी जमीनी हमले शुरू कर सकता है। ट्रंप की ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब ट्रंप प्रशासन कैरिबियन सागर में किए गए हमले को लेकर जांच के घेरे में है। बता दें कि इन हमलों में हुए 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ऐसे में इस हमले को लेकर उठ रहे सवाल के बीच ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बचाव किया। साथ ही ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही जमीन पर भी हमले शुरू करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी हमले आसान है, क्योंकि हमें पता है कि ड्रग तस्कर कहां रहते हैं। हम बहुत जल्द हमला शुरू करने वाले हैं।

80 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप प्रशासन पर सवाल : हाल में अमेरिका की ट्रंप प्रशासन को उन नौकाओं पर किए गए हमलों को लेकर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है जिन पर नशा-तस्करी का आरोप था। इन हमलों में अब तक 80 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में ट्रंप ने रक्षा मंत्री हेगसेथ का बचाव करते हुए कहा कि न तो उन्हें और न ही हेगसेथ को दूसरे हमले की जानकारी थी। ट्रंप ने कहा कि मुझे दूसरे हमले के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि एक नाव को निशाना बनाया गया था।

पहले हमला लाइव देखा- हेगसेथ : दूसरी ओर रक्षा मंत्री हेगसेथ ने कहा कि उन्होंने पहला हमला लाइव देखा, लेकिन उसके बाद अपनी अगली मीटिंग में चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे बाद मुझे दूसरे हमले के बारे में पता चला। मैंने कोई जीवित व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि वह नाव पूरी तरह आग में घिरी हुई थी। हालांकि दूसरे हमले को लेकर व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रमुख एडमिरल फ्रैंक मिच ब्रैडली ने दूसरे हमले का आदेश दिया था।

पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लगाई, रैली-जुलूस निकालने पर रोक

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी है। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों और देश में अशांति फैलने के डर के बीच आया है। इसके तहत 3 दिसंबर तक कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने, 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। आदेश में हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम, विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नफरत भरे भाषण देना, पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करना, दो लोगों के एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह रोक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और रावलपिंडी (अडियाला जेल) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के फैसले के बाद आया है। दावा-संदिग्ध संगठन कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की फिराक में आदेश में कहा गया है कि जिला खुफिया समिति ने रिपोर्ट दी है कि कुछ संगठन और तत्व बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करके कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की फिराक में हैं। ये लोग संवेदनशील ठिकानों, सरकारी इमारतों और चुनिंदा जगहों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पीटीआई नेता बोले- कोर्ट आदेश को लागू करने में नाकाम, इमरान से नहीं मिल पा रहे पीटीआई नेता असद कायसर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सांसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे और फिर अपनी धरना अडियाला जेल ले जाएंगे। उन्होंने कहा, 'प्रदर्शन करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोर्ट अपने आदेश को लागू करने में नाकाम रही है और जेल प्रशासन भी कोर्ट के आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं है।' पिछले हफ्ते, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने जेल के बाहर धरना दिया था, जब उन्हें आठवीं बार इमरान खान से मिलने से रोका गया। इसी तरह, खान के परिवार के सदस्यों को कई हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। न्याय राज्य मंत्री बोले- खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी इससे पहले पाकिस्तान के न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने सोमवार को कहा, ' पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की हालत बहुत खराब हो चुकी है।' पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। जियो न्यूज के मुताबिक मलिक ने कहा, 'खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी वहां की स्थिति को सुधारने में बुरी तरह फेल रहे हैं। वह न तो केंद्र सरकार से कोई तालमेल रख रहे हैं और न ही जरूरी जगहों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। सेना के आदेश पर अफरीदी को पुलिस ने पीटा था।

असीम मुनीर के इशारे पर जेल में किया जा रहा टॉर्चर, बहनों से मुलाकात पर इमरान ने क्या बताया

करांची, एजेंसी। इमरान खान की बहनों ने उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. खानम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह (ईश्वर की स्तुति हो), वह ठीक हैं... लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से वह नाराज थे। उन्हें पूरे दिन उनकी कोठरी में बंद रखा जाता है... केवल कुछ समय के लिए ही बाहर निकल सकते हैं और उन्हें किसी से बातचीत करने की अनुमति नहीं है। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के निर्देश पर उन्हें अदियाला जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान को पाकिस्तानी जेल में एकांत कारावास में रखा गया है और बाहरी दुनिया से उनकी कोई पहुँच नहीं है। इमरान खान की बहनों ने उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. खानम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह (ईश्वर की स्तुति हो), वह ठीक हैं... लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से वह नाराज थे। उन्हें पूरे दिन उनकी कोठरी में बंद रखा जाता है... केवल कुछ समय के लिए ही बाहर निकल सकते हैं और उन्हें किसी से बातचीत करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेतृत्व के साथ-साथ उस अलोकतांत्रिक शासन के लिए भी संदेश दिया, जिसे उन्होंने अलोकतांत्रिक शासन कहा था। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इमरान खान ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर उस मानसिक यातना के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसका दावा वे जेल में कर रहे हैं। मुलाकात के बाद बोलते हुए उज़मा खान ने कहा कि इमरान जेल प्रशासन से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर नाराज़ थे, हालाँकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनका 'मनोबल अभी भी ऊँचा है। उज़मा की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पीटीआई ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय और अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किया था और इमरान खान के मुलाकात के अधिकार पर लगाए गए गैरकानूनी प्रतिबंधों की निंदा की थी। पार्टी और परिवार ने बार-बार शिकायत की थी कि सप्ताह में दो बार मुलाकात की अनुमति देने वाले अदालती आदेश के बावजूद, कई हफ़्तों से मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई थी।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

तेज रफ्तार कार हाईवे पर ट्रक में घुसी, चार डॉक्टरों की हुई दर्दनाक मौत

अमरोहा (एजेंसी)। यूपी के अमरोहा जिले के रजबपुर क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार खड़े हुए ट्रक से टकराने के कारण चार चिकित्सकों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बीती देर रात करीब साढ़े 10 बजे अतरासी इलाके के पास यह दुर्घटना हुई। पुलिस के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रक के नीचे फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कटर से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान दिल्ली के निवासी आयुष शर्मा, श्रेष्ठ पंचोली, कोलकाता के निवासी अर्नब चक्रवर्ती और त्रिपुरा के रहने वाले सप्तऋषि के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।

एसिड अटैक मामले में 16 साल बाद भी ट्रायल... अत्याधिक देरी पर भड़के सीजेआई

नई दिल्ली (एजेंसी)। 2009 के एसिड अटैक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त कर कड़ा रुख अपनाया है। साल 2009 में एक महिला पर हुए एसिड अटैक का मामला, जिसका ट्रायल 16 साल बाद भी (खबर के अनुसार) चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली) इसतरह के मामलों को हैंडल नहीं कर सकती है, तब कौन करेगा। उन्होंने शर्म की बात और सिस्टम का मज़ाक बताया। बेंच (सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची) ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से एसिड अटैक केस में लंबित ट्रायल का डेटा चार हफ़्तों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि ट्रायल अब दिल्ली के रोहिणी में अंतिम सुनवाई के चरण में है। वह अपने केस के साथ-साथ अन्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद भी कर रही हैं। सीजेआई ने याचिकाकर्ता को ट्रायल में तेजी लाने के लिए आवेदन दायर करने और मामले की सुनवाई रोज़ाना करने को कहा। याचिकाकर्ता ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स की बुरी हालत (जैसे एसिड पीने को मजबूर होना, आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूब पर निर्भरता) का जिक्र किया और उन्हें दिव्यांगों की कैटेगरी में रखने की मांग की, ताकि उन्हें वैलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल सके। बेंच ने केंद्र से इस अर्जी पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से चल रहे एसिड अटैक ट्रायल की धीमी गति पर न्यायिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है और देश भर के हाई कोर्ट से लंबित मामलों का डेटा मांगा है, साथ ही पीड़ितों को दिव्यांग कैटेगरी में शामिल करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा है।

धर्मेंद्र की संपत्ति को लेकर चर्चा, सनी ने कहा... सभी बच्चों को उनकी संपत्ति में समान अधिका

मुंबई (एजेंसी)। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को उनके मुंबई स्थित घर पर निधन हो गया था। उनकी अनुमानित संपत्ति जो कि करीब 450 करोड़ रुपये है, जिसमें फार्महाउस, बंगला, स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस, रेस्टोरेंट और अन्य निवेश शामिल हैं। इसके बंटवारे को लेकर चर्चा जोरों पर है। बालीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने दो शादिया की थी इसके बाद उनके दो परिवार है। पहली पत्नी प्रकाश कौर से अभिनेता सनी देओल, बॉबी देओल, बहन अजीता और विजेता। जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से ईशा और अहाना देओल शामिल है। इसके अलावा उनके 13 नाती-पोते भी हैं। बात दें कि हेमा और उनकी बेटियों का धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल न होना, परिवार के भीतर संभावित मतभेदों की खबरों को हवा देता है। साथ ही, हेमा मालिनी के 45 साल की शादी में पहली पत्नी वाले घर कभी न जाने का ज़िक्र है, जिसके कारण अंतिम समय में वे धर्मेंद्र से नहीं मिल पाईं। लेकिन परिवार के एक करीबी सूत्र के अनुसार, सनी देओल ने स्पष्ट किया है कि धर्मेंद्र के सभी बच्चों को उनकी संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होगा। सनी का कहना है कि वे किसी भी हालत में ईशा और अहाना के हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचने देने वाले है। उन्होंने कहा कि यह धर्मेंद्र की भी आखिरी इच्छा थी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अब यह देखना होगा कि उनकी इच्छा और सनी देओल के आश्वासन के अनुरूप विरासत को न्यायपूर्ण तरीके से कैसे विभाजित किया जाता है।

800 करोड़ के ऑनलाइन सट्टेबाजी धोखाधड़ी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। सूरत पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने 800 करोड़ के ऑनलाइन सट्टेबाजी धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जतिन ठक्कर उर्फ जॉन रैपर (27) और दीपकुमार ठक्कर (24) को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने इसके पहले सूरत के कतारगाम इलाके में छापेमारी कर मीत शाह, यश शिंदे, ऋषिकेश सपकाल, नीलेश सोलंकी और परेशकुमार मोदी को ऑनलाइन सट्टेबाजी पोर्टल या मंच के जरिए लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर 149 बैंक खातों का उपयोग कर रहे थे और इन खातों के संबंध में पूरे भारत में 417 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। जतिन और दीपकुमार के फरार होने पर सूरत पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।

भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हथियार खरीदने के आरोप में 5 को आजीवन कारावास

कोलकाता(एजेंसी)। कोलकाता की एक कोर्ट ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के पांच सदस्यों को जिनमें से दो बांग्लादेशी नागरिक हैं, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और इस उद्देश्य के लिए हथियार खरीदने का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी समूह जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के कार्यकर्ता भारत के कई राज्यों में बम विस्फोट जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने सितंबर 2016 में पश्चिम बंगाल और असम से छह आरोपियों को विस्फोटक, आईईडी, भारत में विस्फोट करने की उनकी योजना के दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया था। सिटी सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश रोहन सिन्हा ने छह आरोपियों में से पांच को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिकों अनवर हुसैन फारुक और मोहम्मद रुबेल, पश्चिम बंगाल के बर्धमान निवासी मौलाना यूसुफ एस के और असम निवासियों मोहम्मद साहिदुल इस्लाम और जबीरुल इस्लाम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। छठे आरोपी बर्धमान निवासी अब्दुल कलाम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

वायु प्रदूषण पर बोलीं सोनिया गांधी- मुझ जैसे बुजुर्गों को हो रही परेशानी, कुछ करना सरकार की जिम्मेदारी

-संसद परिसर में विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में लगातार वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई और इसे लेकर आज यहां संसद परिसर में विपक्ष ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के सामने मास्क, पोस्टर और स्लोगन के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से त्वरित और ठोस कदम उठाने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेत्री सोनियां गांधी भी शरीक हुईं और वायु प्रदूषण के लिए सरकार को घेरा।

यहां सोनिया गांधी ने कहा, कि वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चे परेशान हैं, मुझ जैसे बुजुर्गों को परेशानी हो रही। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदर्शन में शामिल होते हुए कहा, कुछ करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। छोटे बच्चे परेशान हैं, और मेरे जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए भी यह मुश्किल है। सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने मास्क और स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सोनिया गांधी के बयान को विपक्ष की उस बढ़ती नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है, जो दिल्ली की विषाक्त हवा और केंद्रीय व राज्य सरकारों की निष्क्रियता पर केंद्रित है।

इसी बीच वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, कि आखिर किस मौसम का मजा लें? खासतौर पर तब जबकि लोग सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहे हों। उन्होंने कहा, बाहर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर साल स्थिति बिगड़ती जा रही है, हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हमने सरकार से कहा है कि कार्रवाई करे, हम उसके साथ खड़े हैं। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। उन्होंने वायु गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बताया और इसे संसद में शीर्ष प्राथमिकता से उठाने की आवश्यकता दोहराई।

स्थगन प्रस्ताव दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बताया, कि उन्होंने सदन में काम रोको प्रस्ताव दिया है। उनके अनुसार, दिल्ली में एक्यूआई 400 है, लोग बुरी स्थिति में हैं। बच्चों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ी आपदा है। इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

दोनों सरकारें फेल : अजय माकन

कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, दिल्ली में, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। कोई भी अब ब्लेम गेम नहीं खेल सकता। जब तक दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार नहीं होगा, प्रदूषण का मुद्दा हल नहीं होगा। कांग्रेस के 15 साल में हालात नियंत्रण में थे, लेकिन बीजेपी और आप दोनों दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल हो गए हैं।

प्रदूषण पर कड़ा राजनीतिक दबाव

दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई लगातार 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि स्थितियां बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगियों के लिए बेहद खतरनाक हैं।

यूपी में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से टूटा नाता ! कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक फैसले से सूबे की राजनीति गरमा गयी है। दरअसल, पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। इसके पीछे वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बताया जाता है कि यूपी कांग्रेस सांसदों की राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अलग से पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से अब इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं राजनीतिक जानकार कांग्रेस के इस फैसले को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक नए प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। हमारा गठबंधन जारी रहेगा। मगर, कांग्रेस पार्टी के इस फैसले ने सभी को चौका दिया है। हालांकि, कांग्रेस के इस निर्णय पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा-कांग्रेस के गठबंधन प्रदेश की 80 सीटों सें 43 सीटें अपने खाते में की थी।

झांसी की एसआईआर लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम, मचा हड़कंप

- मकान नंबर 54 में दर्ज है नाम लेकिन वहां मंदिर मिला

झांसी (एजेंसी)। यूपी इन दिनों एसआईआर प्रक्रिया चर्चाओं में हैं। आए दिन इसको लेकर कुछ न कुछ चौंकाने वाली मामले सामने आ रहे हैं। अब एक और अजब-गजब मामला सामने आया है। जहां एसआईआर सूची में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम दर्ज मिला है, जिसको लेकर अब हड़कंप मचा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे नाम सूची में कैसे पहुंचे?

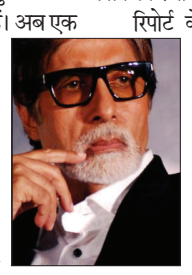

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ओरछा गेट बाहर के खुशीपुरा इलाके की वोटर लिस्ट में उनका नाम और मकान नंबर 54 दर्ज है। साफतौर से ये भी बताया गया है कि अमिताभ बच्चन ने साल 2003 में वोट भी डाला था, साथ ही लिस्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन की उम्र 76 साल की है। इसको लेकर जब पड़ोसियों ने बताया तो हर कोई हैरान रह गया। पड़ोसियों ने कहा कि हमने अमिताभ बच्चन को सिर्फ फिल्मों में देखा है।

रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर लिस्ट में अमिताभ बच्चन के नाम के साथ जो मकान नंबर-54 दर्ज है वह मकान नंबर सुरेंद्र कुमार (76) पुत्र राजेश कुमार के नाम दर्ज पाया गया है। दोनों मतदाताओं का नाम लिस्ट में 543 और 544वें नंबर पर देखा गया है। वहीं पूरा मामले में यूटर्न तब आया जब मकान नंबर 54 की जगह यहां मंदिर मिला। नाम सामने आते ही प्रशासन में खलबली मच गई। विभाग में घमासान और जांच की मांग तेज हो गई है। फिलहाल विभाग में जवाबदेही को लेकर चर्चाएं तीखी हो गई हैं और मामला गर्माता जा रहा है।

सीएम रेंवत के बयान पर बीजेपी का आरोप, हिंदू-विरोधी राजनीति कर रहे है और मुस्लिम लीग जैसी सोच

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी-देवताओं पर दिए गए बयान से विवाद पैदा हो गया है। सीएम रेड्डी ने कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में पार्टी के भीतर विभिन्न विचारधाराओं और समूहों को समायोजित करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की विविधता का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के तीन करोड़ देवी-देवता हैं, और हर परिस्थिति के लिए अलग देवता माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने विभिन्न देवताओं के उदाहरण दिए, जैसे अविवाहितों के लिए हनुमान, दो बार शादी करने वालों के लिए अलग देवता, शराब पीने वालों के लिए अलग देवता, आदि। सीएम रेंवत के बयान पर भाजपा और बीआरएस (बीआरएस) दोनों ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त देकर मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हिंदू-विरोधी राजनीति कर रही है और मुस्लिम लीग जैसी सोच के साथ काम कर रही है। भाजपा के

राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान और अर्बन नक्सली मानसिकता का उदाहरण बताया। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू आस्थाओं पर बार-बार हमला करने का आरोप लगाया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के राधे-राधे अभिवादन पर आपत्ति जताने की घटना का भी उल्लेख किया। भाजपा ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जिहाद संबंधी टिप्पणी के समर्थन और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की भौं-भौं वाली प्रतिक्रिया पर भी निशाना साधा, इसे कांग्रेस के मुस्लिम लीग एजेंडा का हिस्सा बताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बयान को आपत्तिजनक और घृणित बताते हुए कांग्रेस के भीतर हिंदू-विरोधी भावनाओं का जहर उजागर होने की बात कही।

इसके बाद में मुख्यमंत्री रेड्डी ने दावा किया कि भाजपा उनके बयान को तोड़-मरोड़ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बात कांग्रेस के भीतर की आंतरिक विविधता को समझाने के लिए कही थी ताकि नए डीसीसी अध्यक्ष सभी को साथ लेकर चल सकें। यह विवाद तब सामने आया है जब तेलंगाना की नई कांग्रेस सरकार संगठन को मजबूत करने और व्यापक समूहों तक पार्टी की विचारधारा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। यह घटना तेलंगाना की राजनीति में एक तीखी बहस का विषय बन गई है, जिसमें विपक्षी दल कांग्रेस पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने और मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं।

राहुल गांधी की नागरिकता को दाखिल परिवाद पर सुनवाई आज

नई दिल्ली(एजेंसी)। रायबरेली (ईएमएस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल परिवाद पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा। बेंगलुरु के रहने वाले भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता विंदेश्वरी पांडेय के माध्यम से बुधवार को प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर कोर्ट ने शहर कोतवाली पुलिस से प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है।

एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 335, 340, 236, 237, 61, 148,147, 152, 238, 336, 351, 354,359, 241 सहित पासपोर्ट अधिनियम व विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश डा. विवेक कुमार के समक्ष दाखिल किया है। कोर्ट ने न्यायालय ने प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश करने के पूर्व कोतवाली से रिपोर्ट मंगाई है। शिकायतकर्ता ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ धाराओं में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान है। दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट, गोपनीय सूचना दुश्मनों को पहुंचाना, बेनामी संस्था बनाने जैसे गंभीर आरोप है। कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद में दर्ज कर सुनवाई के लिए कल पांच दिसम्बर की तिथि नियत की है।

भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एलीकेशन दी गयी है। कोर्ट से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में न्यायालय ने कोतवाली पुलिस रायबरेली से रिपोर्ट मांगी है। जांच की रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाएगी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई पहले से जांच कर रही है। शिशिर ने कहा कि भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विदेशी नागरिक हमारे संसद में 20 साल से बैठे हैं। इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार से भी पासपोर्ट आ गया है। भारतीय सरकार से भी हमें जानकारी मिली है। जो भी डॉक्यूमेंट न्यायालय मांगेगा या पुलिस मांगेगी, उसमें पूरी सहायता करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं।

जीव दया और कबूतर बचाव अभियान के तहत जैन समुदाय 7 दिसंबर को मुंबई में मार्च निकालेगा

मुंबई (एजेंसी)। जैन समुदाय 7 दिसंबर को मुंबई में एक बड़ा मार्च निकालेगा। जीव दया और कबूतर बचाव अभियान की शुरुआत जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय महाराज के नेतृत्व में शुरू किया जाएगा। यह मार्च कोलाबा जैन मंदिर से शुरू होगा और लालबाग, भायखला, डोंगरी, लोअर परेल होते हुए दादर कबूतरखाना जैन मंदिर और दूसरे बड़े जैन मंदिरों तक जाएगा। मार्च के दौरान जैन समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रवचन और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान को बड़े पैमाने पर समर्थन देने की अपील भी की जाएगी। खबर है कि नीलेशचंद्रजी महाराज जीव दया और कबूतर बचाव आंदोलन को और मजबूत करने के लिए दादर में फिर से अनशन करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का ध्यान खींचने के लिए जैन समुदाय के आक्रामक रुख अपनाने की संभावना है। नीलेशचंद्र महाराज कहते हैं कि जैन समाज ने किसी के मंदिर या घर तोड़कर जैनालय नहीं बनाया। यह जैन समाज शांतिप्रिय समाज है। लेकिन हमारे विले पार्ले का मंदिर बुलडोज़र से गिरा दिया गया, तो उन्होंने गैर-कानूनी मस्जिदें क्यों नहीं गिराईं? दो नेता मुझसे मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम 15 दिन बाद कोई हल निकालेंगे, लेकिन बात नहीं बनी। देवेंद्र फडणवीस के साथ जो गद्दार नेता समाज को तोड़ रहे हैं, उनकी खैर नहीं है। मेरी जान भी चली जाए, तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो मैसेज देना था, वह मैंने देवेंद्र फडणवीस को दे दिया है। जो भी हिंदी के हित में कुछ करेगा, हम उसका साथ देंगे। क्या जैन समाज आने वाले चुनाव लड़ेगा? इसपर जैन मुनि नीलेशचंद्र जी ने कहा, हां, मैं पूरे भारत में अभियान शुरू करूंगा, हर समाज की एक पार्टी होती है। तो जैन समुदाय के लिए कोई पार्टी क्यों नहीं है, हमें कुछ चीज़ों के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है। हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। हम एक शांतिप्रिय और प्यार करने वाला समुदाय हैं। हम किसी के झगड़ों में नहीं पड़ते। हम लड़ाई-झगड़ों में नहीं पड़ते। जब विदर्भ में बाढ़ आई थी, तो मैंने वहां दो करोड़ रुपये भेजे, हमने देवेंद्र फडणवीस को चेक दिया, हमने महाराष्ट्र के लोगों के लिए दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं।

बिहार चुनाव की नाराजगी के बाद झारखंड में उबाल: हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जा सकते हैं?

रांची (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की नाराजगी। बिहार चुनाव में जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिससे पार्टी बेहद खफा है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में तेज चर्चा है कि जेएमएम एनडीए के साथ जा सकती है और झारखंड में नई सरकार बन सकती है।

2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। 81 में से 56 सीटें जीती थीं - जेएमएम 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और वाम दल 2। बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें मिली थीं। अगर जेएमएम महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आती है तो सिर्फ दो दलों की सीटें (34 + 20 = 54) ही बहुमत के जादुई आंकड़े 42 से कहीं ऊपर पहुँच जाएंगी। अगर पूरा एनडीए जेएमएम के साथ आता है तो तस्वीर और मजबूत होगी। बीजेपी (20) + जेएमएम (34) + आजसू (1) + एलजेपी (1) + जेडीयू (1) = कुल 57 सीटें। यानी भारी बहुमत। इससे मौजूदा महागठबंधन सरकार अपने आप गिर जाएगी और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस बार बीजेपी के समर्थन से। सियासी जानकार मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की जीत और राजद की हार के बाद जेएमएम को लगा कि कांग्रेस-राजद के साथ रहने से उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। बिहार में सीट न मिलना आखिरी झटका साबित हुआ। यही वजह है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ अफवाह है। हम महागठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। मगर दिल्ली में सोरेन दंपती की मौजूदगी और बंद कमरों में चल रही बैठकों ने सारी अटकलों को हवा दे दी है। अगर यह उलटफेर हुआ तो झारखंड की राजनीति में पिछले दस साल का सबसे बड़ा सियासी धमाका होगा। देखना यह है कि हेमंत सोरेन पुरानी दोस्ती निभाते हैं या नया गठबंधन चुनते हैं।

बाबरी से मिलती-जुलती मस्जिद बनाने का दावा करने वाले कबीर टीएमसी से निलंबित

कोलकाता (एजेंसी)। बाबरी से मिलती जुलती मस्जिद बनाने का दावा कर रहे विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया है। कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद की नींव रखने की बात कही थी। इसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी विधायक कबीर के इस फैसले से सीएम ममता बनर्जी नाराज थीं। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

पुतिन का दौरा अहम, तकनीक-ऊर्जा सहयोग और यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा

-पूर्व राजनयिक त्रिगुणायत ने कहा- कंपनियों को सामरिक रिश्तों का लाभ उठाना चाहिए।

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। पुतिन की यात्रा को लेकर पूर्व भारतीय राजनयिकों का मानना है कि परमाणु प्लांट से जुड़े विषय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक के अलावा पुतिन और पीउम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है। पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि रूस हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा है। इस कड़ी में 25 साल पहले यह तय हुआ कि समय-समय पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। उसी आधार पर पुतिन भारत आ रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि पिछले 25 सालों में भारत-रूस संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आपसी समझ भी काफी अच्छी है। रूस-यूक्रेन युद्ध पर त्रिगुणायत ने कहा कि संभावना है कि पुतिन बातचीत में पीएम मोदी से यूक्रेन के विषय पर बात कर सकते हैं। पीएम मोदी ने हमेशा युद्धविराम की बात की है। रूस-यूक्रेन की लड़ाई इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।

त्रिगुणायत ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी में रूस की बहुत बड़ी भूमिका है। उसके चलते भारत के ऊपर कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लगा है। हालांकि, भारत ने इतना ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि द्विपक्षीय वार्ता में इस पर भी चर्चा हो सकती है। अगर रूस अपने सरप्लस को रणनीतिक तरीके से भारत में निवेश करना चाहे तो वह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसी तरह भारतीय कंपनियों के लिए भी यह बड़ा मौका है। कंपनियों को भी सामरिक रिश्तों का लाभ उठाना चाहिए।

वहीं, पूर्व राजनयिक वीना सिकरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुतिन का यह एक बहुत ही अहम दौरा है। इसके पीछे कई कारण हैं। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल हालात बहुत नाजुक हैं। दो युद्ध चल रहे हैं, जो अभी खत्म नहीं हैं, बल्कि तनाव बना हुआ है। इसके अलावा भारत पर अमेरिका की तरफ से ज्यादा टैरिफ को लेकर काफी दबाव है, जिसका ज्यादातर हिस्सा उस एनर्जी से जुड़ा है जो भारत रूस से खरीद रहा है। सिकरी ने कहा कि रूस की ओर से विकसित सुखोई-57 स्टील्थ फाइटर जेट बहुत अहम है और भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।